राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 305

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 12 अप्रैल 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 14

ट्रंप ने कहा–अमेरिका में लॉकडाउन की समाप्ति होगा जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला >>11

कोरोनामीटर

(स्रोत : वर्ल्डोमीटर्स डॉट इंफो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

	विश्व	अमेरिका	स्पेन	भारत	5 अप्रैल की स्थिति	वृद्धि दर	दिल्ली
कुल केस	17,14,733	5,05,237	1,61,852	8,279	3,494	137%	1,069
मौतें	1,03,803	20,057	16,353	279	100	179%	19
स्वस्थ हुए	3,88,866	27,314	59,109	845	200	322%	26

भारत के प्रमुख राज्य

राज्य	केस	मौतें
महाराष्ट्र	1,761	127
तमिलनाडु	969	10
राजस्थान	700	9
मध्य प्रदेश	595	40
तेलंगाना	487	12
उत्तर प्रदेश	456	5
आंध्र प्रदेश	405	6
केरल	373	3
अन्य	1,464	48

रात 11:30 बजे तक

अन्य प्रमुख देश

देश	इटली	फ्रांस	जर्मनी
केस	1,47,577	1,24,869	1,22,171
मौतें	19,468	13,197	2,736

नोट : कोरोना से प्रभावित लोगों के संदर्भ में आंकड़े उल्लिखित दो सोतों के अतिरिक्त जागरण न्यूज नेटवर्क के रूप में अन्य माध्यमों से भी लिए गए हैं। अत : तालिका तथा दैनिक जागरण के इस अंक में प्रकाशित सामग्री में आंकड़ों का अंतर संभव है।

हेल्पलाइन नंबर

कोरोना से जुड़ी सही जानकारी देने के लिए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों को मोबाइल में सुरक्षित करके कोई भी प्रामाणिक सूचना पाई जा सकती है। कृपया नंबर दर्ज करके वाट्सएप पर सिर्फ नमस्कार का संदेश भेजें। तुरंत एक मेन्यू आएगा, जिसके अनुसार वांछित जानकारी ली जा सकती है।

who:+41 798931892

mygov : +919013151515

तेलंगाना, बंगाल और महाराष्ट्र में लॉकडाउन 30 तक बढ़ा • पेज 4

महाराष्ट्र में 1,761 व देश में आठ हजार से ज्यादा संक्रमित • पेज 5

टाटा ने बढ़ाया मदद का हाथ, चालू होगा रुद्रपुर अस्पताल • पेज 6

Fact Check News

लॉकडाउन में मजदूरों की पिटाई के दावे निकले गलत

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 4

सरोकार

नारियल का तेल करेगा कोरोना को फेल!

वाराणसी : नारियल के तेल में पाया जाने वाला एक विशेष अम्ल कोरोना वायरस का खेल खत्म कर सकता है। अब तक अनेक घातक रोगाणुओं पर यह अम्ल प्रभावी सिद्ध हुआ है। मेडिकल जगत में इसे लेकर मंथन हो रहा है। (पेज-6)

रविवार विशेष

बिग बॉस के घर में रहने से कहीं आसान है लॉकडाउन

कोलकाता : लकवे को मात देकर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके पहलवान संग्राम सिंह अब कोरोना को हराने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़े हुए हैं। (पेज-6)

कोरोना के इलाज के लिए राज्यों को और वित्तीय पैकेज संभव

नई दिल्ली : कोरोना के इलाज के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से अभी और वित्तीय पैकेज मिल सकता है। भारत में अधिकतर राज्यों ने चालू वित्त वर्ष (2020-21) में स्वास्थ्य सेवा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का अधिकतम दो फीसद खर्च करने का प्रावधान किया है। लेकिन कोरोना के बढ़ते फैलाव को देखते हुए उन्हें इस खर्च को बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य सेवा पर राज्य अपने जीडीपी (जीएसडीपी) का एक फीसद भी अतिरिक्त खर्च करते हैं तो उनका राजकोषीय घाटा तीन फीसद के पार जा सकता है। इसलिए केंद्र की तरफ से उन्हें और वित्तीय मदद दी जा सकती है। (पेज-10)

दो हफ्ते और बढ़ेगा लॉकडाउन

तैयारी ▶ 'जान भी, जहान भी' के नए मंत्र के साथ कुछ कारोबारी गतिविधियों को अनुमति के संकेत

पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में बनी सहमति, अब 30 अप्रैल तक लॉकडाउन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मोदी एक-दो दिन में करेंगे औपचारिक एलान, कुछ राज्यों ने पहले ही कर दी घोषणा
- लॉकडाउन होगा सख्त, मगर थमे आर्थिक पहिए को शुरू करने के लिए उठेंगे कदम
- पीएम का मुख्यमंत्रियों को भरोसा- मैं 24 घंटे उपलब्ध, जरूरत पर जब चाहें तब संपर्क कर सकते हैं

देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। एएनआइ

मास्क में नजर आए मोदी

कोरोना से लड़ाई में मास्क बचाव का पहला रक्षा कवच है, इसका संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मास्क लगाया। चार घंटे से अधिक चली बैठक के दौरान प्रधानमंत्री हाथ से बना सफेद मास्क लगाए हुए थे। कई राज्यों के सीएम भी मास्क लगाकर बैठक में शामिल हुए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जैसे कुछ एक मुख्यमंत्री गमछे को मास्क के विकल्प के रूप में उपयोग करते दिखाई दिए।

तीन जोन में बंटेंगे क्षेत्र

- लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार बदली पाबंदियों के साथ क्षेत्रवार रणनीति पर विचार कर रही है। यह रणनीति देशव्यापी लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक्जिट प्लान की तरह भी काम करेगी।
- रेड जोन : जिन जिलों में संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं, उन जिलों को पूरी तरह सील रखा जाएगा। वहां आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त किसी को अनुमति नहीं होगी।
- ऑरेंज जोन : जहां मामले नियंत्रित हैं और नए मामले नहीं आ रहे, वहां सतर्कता के प्रावधानों के साथ सीमित आवाजाही और कृषि से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति मिलेगी।
- ग्रीन जोन : जिन जिलों में कोई संक्रमित नहीं, वहां कृषि के साथ-साथ कुछ एमएसएमई इकाइयों को सशर्त संचालन की अनुमति होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

कुछ और भी तैयारियां

- राज्यों की मांग को देखते हुए शराब की दुकानें खोलने पर विचार। राज्यों के लिए यह राजस्व का बड़ा जरिया है।
- कुछ क्षेत्रों में 30 प्रतिशत या इससे कम यात्रियों के साथ घरेलू हवाई व रेल यातायात के संचालन को भी मंजूरी संभव।
- दिल्ली जैसे शहरों में 30 प्रतिशत या कम यात्रियों के साथ मेट्रो व सार्वजनिक परिवहन की बसें भी चल सकती हैं।
- क्वारंटाइन केंद्रों की सीमित क्षमता को देखते हुए कोई भी राज्य अभी बड़ी संख्या में आवाजाही के पक्ष में नहीं।

मद्देनजर अगले चरण की रणनीति में उन इलाकों में सीमित आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का संकेत भी दिया जहां कोरोना महामारी का असर नहीं है। पीएम ने कहा कि जहां मौजूदा 21 दिन के लॉकडाउन में जिंदगी बचाने के सबसे अहम लक्ष्य के लिए 'जान है तो जहान है' मुख्य मंत्र है। वहीं दूसरे चरण में सरकार का मंत्र 'जान भी, जहान भी' रहेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से यह अनुरोध भी किया कि राज्यों को उनकी सीमा के भीतर सतर्कता के साथ आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जाए। ऐसा नहीं होने से राज्यों के समक्ष बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा।

केंद्र की ओर से लॉकडाउन बढ़ाने का यह संकेत मिलते ही बैठक के तुरंत बाद महाराष्ट्र और बंगाल की मुख्यमंत्री ने इसे अपने सूबों में 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा भी कर डाली। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम के फैसले को सही ठहराने के बहाने बड़ी चतुराई से लॉकडाउन दो हफ्ते बढ़ाए जाने का निर्णय उजागर कर दिया। कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री के साथ पीएम की यह तीसरी बैठक थी। इसमें लॉकडाउन बढ़ाने ही नहीं बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के लिए केंद्र की ओर से तैयार की गई योजना पर भी बातचीत हुई।

निरंतर सतर्कता की जरूरत : पीएम ने कहा कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में निश्चित रूप से मदद मिली है। लेकिन स्थिति तेजी से बदल रही है ऐसे में निरंतर सतर्कता सर्वोपरि है। मोदी ने कहा कि वायरस का संक्रमण रोकने के लिए उठाए गए कदमों का असर जानने के लिए अगले तीन-चार हफ्ते बेहद अहम हैं। दवाओं की कमी को लेकर कुछ क्षेत्रों में जताई जा रही चिंता पर पीएम ने मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया कि आवश्यक दवाओं की देश में पर्याप्त उपलब्धता है।

अव्यवस्था पर दिखाएं सख्ती पेज>>4

केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष अफसरों को कल से काम पर लौटने का निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन की अवधि भले ही बढ़ने जा रही हो, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने का काम शुरू होने जा रहा है। सभी मंत्रालयों को ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए नए सिरे से योजना बनाने के लिए कहा गया है।

शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद सभी केंद्रीय मंत्रियों को सोमवार से मंत्रालय का कामकाज शुरू करने के लिए कहा गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक सभी मंत्रियों के साथ संयुक्त सचिव एवं उनसे ऊपर के सभी अफसरों को भी सोमवार से मंत्रालय में अपने काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मंत्रालयों में एक तिहाई आवश्यक कर्मचारियों को भी काम पर आने के लिए कहा गया है। इन लोगों को शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए कामकाज शुरू करने को कहा गया है। मंत्रालयों के खुलने के बावजूद बाहरी लोगों का प्रवेश मंत्रालय और सरकारी विभागों में वर्जित होगा।

सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से या पूरी तरह से खोलने पर बिल्कुल नए माहौल में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना होगा। इसकी तैयारी पहले से रहनी चाहिए। इसी को देखते हुए ही मंत्रियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है ताकि वे अपने-अपने मंत्रालय का काम प्रभावी तरीके से शुरू कर सकें। मंत्रालय इस वरीयता को भी तय करेंगे कि कौन से काम पहले किए जाने चाहिए और कौन से बाद में।

लॉकडाउन के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना है। आर्थिक उत्पादन चरणबद्ध तरीके से शुरू कर इन लोगों की रोजी-रोटी के इंतजाम के साथ रोजाना हो रहे हजारों करोड़ों के नुकसान को भी कम करने की योजना है।

कोविड-19 वायरस की चेन को तोड़ने के लिए गत 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है जिसकी अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है। इस दौरान सभी मंत्री एवं मंत्रालय के अधिकारी घर से काम कर रहे हैं और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक-दूसरे से संपर्क में हैं। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी ही बाहर निकल कर काम कर रहे हैं।

संयुक्त सचिव व उनसे ऊपर के अधिकारियों को आना होगा दफ्तर

कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (एससीटीआइएमएसटी) को कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इसके तहत ठीक हो चुके व्यक्ति में विकसित प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल बीमार व्यक्ति के इलाज में किया जाता है। एससीटीआइएमएसटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, 'एससीटीआइएमएसटी' राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और उसे कोविड-19 मरीजों के इलाज की अनुमति प्रदान कर दी गई है। वहीं, आइसीएमआर ने बताया है कि उसने शुक्रवार तक कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए 1,61,330 टेस्ट किए हैं।

सेट टॉप बॉक्स में भी हो सकेगी पोर्टेबिलिटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने डीटीएच और केबल सर्विस की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव की नींव रख दी है। नियामक ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सिफारिश की है कि सभी सेट टॉप बॉक्स को इंटर ऑपरेबल बनाना अनिवार्य किया जाए। इसके लिए संबंधित कानूनों में जरूरी प्रावधान करने को कहा गया है। ऐसा होने से डीटीएच और केबल सर्विस में भी पोर्टेबिलिटी संभव होगी यानी बिना सेट टॉप बॉक्स बदले किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से सेवा ले सकेंगे। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने और सेवा बेहतर होने की उम्मीद है।

ट्राई ने अपनी सिफारिश में कहा, 'देश में सभी सेट टॉप बॉक्स को तकनीकी तौर पर इंटर ऑपरेबिलिटी में सक्षम होना चाहिए।' इस काम के लिए कंपनियों को छह महीने का समय देने की बात कही गई है। नियामक ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को भी कहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ट्राई, भारतीय मानक ब्यूरो और टीवी विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों को बतौर सदस्य शामिल करने को कहा गया है। कमेटी के गठन से सेट टॉप बॉक्स को लेकर नए मानक निर्धारित करने के काम को गति मिलेगी। ट्राई ने सेट टॉप बॉक्स के साथ-साथ सभी टीवी निर्माताओं को भी ऐसे डिजिटल टीवी बनाने का निर्देश देने को कहा है, जिनमें यूएसबी पोर्ट बेस्ड कॉमन इंटरफेस हो। इसका अर्थ है कि सभी डिजिटल टीवी में अनिवार्य रूप से एक ऐसा ओपन यूएसबी पोर्ट होगा जिससे डीटीएच या केबल सर्विस को कनेक्ट किया जा सकेगा।

- ट्राई की सिफारिश – इंटर ऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स बनाना हो अनिवार्य
- बॉक्स बदले बिना ही ले सकेंगे मनचाहे सर्विस प्रोवाइडर की सेवा

क्या है इंटर ऑपरेबिलिटी

सेट टॉप बॉक्स के इंटर ऑपरेबल होने का मतलब है कि वह तकनीकी रूप से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस को सपोर्ट कर सकेगा। इसमें सैटेलाइट के जरिये सेवा देने वाले डीटीएच ऑपरेटर और केबल नेटवर्क के जरिये सर्विस देने वाले ऑपरेटर भी शामिल हैं। ग्राहक किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से या बाजार में किसी ओपन सोर्स से सेट टॉप बॉक्स खरीदकर इस्तेमाल कर सकेगा।

क्या है आपका फायदा

अभी ग्राहक को सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ही सेट टॉप बॉक्स मिलता है। सर्विस प्रोवाइडर बदलने के लिए सेट टॉप बॉक्स भी बदलना पड़ता है। इस कारण से कई बार ग्राहक चाहकर भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं बदलता है। ट्राई का कहना है कि इस कारण से इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सर्विस क्वालिटी सुधारने की दिशा में कुछ खास काम नहीं हो पा रहा है।

नए नियमों से चलेंगे मॉल और सिनेमा हॉल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मॉल, सिनेमा हॉल व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नए नियमों के अनुसार काम करना पड़ सकता है। छोटे-बड़े कारखानों के लिए भी इसी प्रकार के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस संबंध में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के डेवलपर्स और औद्योगिक जगत के साथ विचार-विमर्श हो रहा है। हवाई यात्रियों के लिए भी नए नियम बनाए जा रहे हैं।

लॉकडाउन खोलने से पहले सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि औद्योगिक संगठन फिक्की ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने के लिए सरकार से गुजारिश की है ताकि उत्पादन शुरू हो सके।

मॉल के संचालक डेवलपर्स ने बताया कि सरकार की तरफ से मिल रहे संकेत के मुताबिक लॉकडाउन के बाद उन्हें कई नियमों का पालन करना होगा। इंट्री गेट पर ही शरीर का तापमान चेक करने की व्यवस्था करनी होगी। एक ही प्रकार की दुकानों को ऑड एंड इवेन तरीके से खोलना पड़ सकता है। दुकान का आकार छोटा होने पर दुकान में एक बार में एक या दो ग्राहकों को ही प्रवेश की इजाजत होगी। इसी तरह सिनेमा हॉल में एक-दूसरे के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बरकरार रखते हुए बैठने के नियम बन सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों में एक शिफ्ट में आधे लोगों को ही बुलाने या फिर वैकल्पिक दिनों पर श्रमिकों को बुलाने के नियम बनाए जा सकते हैं।

सीआइएसएफ ने विमान यात्रियों के लिए बनाई नई योजना : हवाई जहाज के लिए पहले से ही यह चर्चा चल रही है कि वह अपनी क्षमता के मुकाबले 50 फीसद यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति देंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी योजना में कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। उन्हें मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजरों से लैस होना चाहिए। सीआइएसएफ ने नई योजना में कहा कि हर दो लोगों के बीच खाली सीट के साथ उड़ान भरना हवाई यात्रियों के लिए नया तरीका हो सकता है।

सीआइएसएफ के विशेष निदेशक जीए गणपति ने कहा कि हमने अपनी योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेज दी है।

लॉकडाउन के बाद...

- मॉल में लागू हो सकता ऑड इवेन फार्मूला, इंट्री पर जांचा जाएगा तापमान
- सिनेमा हॉल में दो लोगों के बीच एक मीटर का रखा जा सकता फासला
- हवाई सफर में एक सीट छोड़कर बैठाए जाएंगे यात्री
- कारखानों में भी कम श्रमिकों के साथ शुरू कराया जा सकता उत्पादन

प्रतीकात्मक।

संभले हालात

गणितीय आकलन से लगाया गया लॉकडाउन और कंटेनमेंट उपायों के प्रभाव का अनुमान, नए अनुमान के आधार पर और अधिक स्थापित हुआ है लॉकडाउन का महत्व...

लॉकडाउन न होता तो लाखों में होती मरीजों की संख्या

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 15 अप्रैल तक आठ लाख पार कर जाती कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या
- बिना लॉकडाउन के सिर्फ कंटेनमेंट से 1.20 लाख पहुंचता आंकड़ा
- 25 मार्च से देश भर में लागू किया गया है लॉकडाउन का फैसला

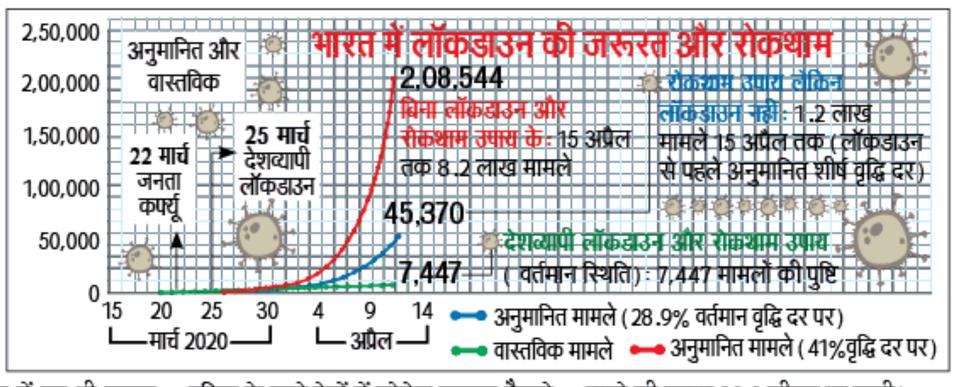

आखिरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने मान ही लिया कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के कदम नहीं उठाए जाते तो 15 अप्रैल तक देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 8.2 लाख तक पहुंच जाती। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ऐसे किसी आकलन से इन्कार किया था, लेकिन शनिवार को उन्होंने माना कि एक गणितीय आकलन में लॉकडाउन और कंटेनमेंट के उपायों का कोरोना के मरीजों की संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया गया है।

गणितीय आकलन के बारे में बताते हुए लव अग्रवाल ने कहा कि यदि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद 25 मार्च से देश में लॉकडाउन नहीं किया जाता और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के कड़े कदम नहीं उठाए जाते तो अब तक कोरोना से ग्रसित मरीजों की संख्या 2,08,544 हो जाती और 15 अप्रैल तक यह बढ़कर आठ लाख 20 हजार पहुंच जाती। इस आकलन में यह भी बताया गया है कि यदि सिर्फ कंटेनमेंट के कदम उठाए जाते और लॉकडाउन लागू नहीं किया जाता, तब भी कोरोना के मरीजों की संख्या अभी तक 45,370 हो जाती और 15 अप्रैल तक एक लाख 20 हजार पहुंच जाती। लॉकडाउन और कंटेनमेंट के उपायों को लागू करने का ही परिणाम है कि अभी देश में केवल 7,529 कोरोना के मरीज हैं। गणितीय आकलन में दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार के आधार पर अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार यदि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के उपाय नहीं किए जाते तो वायरस के मरीजों की संख्या हर दिन 41 फीसद की दर बढ़ती जो 15 अप्रैल तक आठ लाख 20 हजार तक पहुंच जाती। वहीं यदि केवल कंटेनमेंट के उपाय किए जाते और लॉकडाउन लागू नहीं किया जाता तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की रफ्तार 28.9 फीसद रह जाती।

अग्रवाल ने साफ किया कि यह केवल गणितीय आकलन है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) का इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आइसीएमआर ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

आकलन से साबित हुई उपयोगिता पेज>>5

जमात मामले पर मनीष तिवारी बोले– गलत को गलत कहना ही होगा

संजय मिश्र, नई दिल्ली

मनीष तिवारी फाइल

कांग्रेस नेता ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को जमात से सावधान रहने की जरूरत भी बताई

समावेशी समाज के साथ प्रगतिशील सियासत की पैरोकारी करने वाले लोगों ने भी कोरोना महामारी के गंभीर खतरों के बीच तब्लीगी जमात के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर आपत्ति जताई है। इनका मानना है कि कोरोना संक्रमण की चुनौती के इस दौर में तब्लीगी जमात की ऐसी भूमिका के खिलाफ कथित बुद्धिजीवी वर्ग को मुखर रूप से आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस के तेजतर्रार नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ऐसे ही लोगों में हैं जिन्होंने तब्लीगी जमात के जमावड़े और कोरोना पर उसके गैरजिम्मेदार व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाते उसकी तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि गलत को गलत कहना ही होगा।

तिवारी को जमात पर तीखे सवाल उठाने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ जवाबी आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। दरअसल, इस बहस की शुरुआत भी तिवारी ने ही की, जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि तब्लीगी जमात से भारत ही नहीं पूरी दुनिया को सावधान रहना होगा। उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री का वीडियो बयान टैग कर उसका हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान के ज्यादातर कोरोना संक्रमण के मामले जमात से जुड़े हैं।

कथित प्रगतिशील वर्ग में तब्लीगी जमात को लेकर निंदा का सुर धीमा दिखा है पेज>>4

17 हजार 449 कॉल अब तक दिल्ली पुलिस को मिली हैं मदद के लिए। ऐसे परिवारों को भोजन और राशन उपलब्ध कराया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 12 अप्रैल 2020

कोरोना मीटर

दिल्ली-एनसीआर

	ताजा मामले	एक दिन पूर्व के मामले	वृद्धि/कमी दर (% में)	कुल मामलों की स्थिति: कुल मामले	मौतें	बचाए गए	एक सप्ताह पहले की स्थिति: कुल मामले	मौतें	बचाए गए	साप्ताहिक वृद्धि दर (% में): कुल मामले	मौतें	बचाए गए
गाजियाबाद	03	01	200	30	0	03	13	0	03	130.76	0	0
गौतमबुद्ध नगर	0	02	-200	64	0	12	58	0	10	10.34	0	20
दिल्ली	166	183	90	1069	19	26	445	6	15	140.22	216.66	73.33
फरीदाबाद	03	00	300	31	00	03	14	00	01	121.42	0	200
गुरुग्राम	02	03	66	38	01	14	12	01	04	216.66	0	250

न्यूज गैलरी

लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का आदेश

नई दिल्ली : मुख्य सचिव विजय देव ने जिला राजस्व उपायुक्तों व जिला पुलिस उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कहा कि शारीरिक दूरी का पालन कराया जाए। सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। जो लोग आदेश को नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर्विलांस एप से सील कॉलोनियों के आसपास के क्षेत्र पर भी नजर रखें। उन्होंने आदेश में कहा कि सभी सील की गई कॉलोनियों में कोरोना मरीज समूह है। यहां से कोरोना अन्य कॉलोनियों में न फैले इसलिए सख्ती जरूरी है। (जासं)

बारात घर भी नाइट शेल्टर में तब्दील करेगा एनडीएमसी

नई दिल्ली : कोरोना से जंग में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) भी अपनी तरफ से नागरिकों की सहायता करने के लिए कदम उठा रही है। इसके तहत अब एनडीएमसी ने अपने दो बरात घरों को नाइट शेल्टर में तब्दील करने का फैसला लिया है। एनडीएमसी के अनुसार सरोजनी नगर के बारात घर और पालिका धाम के सामुदायिक केंद्र को जिला प्रशासन को दे दिया है। इसमें अस्थायी रूप से नाइट शेल्टर स्थापित किया जा सकता है। वहीं, नई दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग और बापू धाम के बारात घरों को लॉकडाउन प्रबंधन में लगे अतिरिक्त पुलिस बल के जवानों को रहने के लिए दिल्ली पुलिस को प्रदान किया गया है। इसके साथ ही नौ सामुदायिक केंद्रों को नई दिल्ली जिला प्रशासन की आवश्यकता पर आवश्यक सेवाओं पर तैनात अधिकारियों/चिकित्सा कर्मचारियों के रात्रि निवास के लिए भी प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही 30 मार्च तक सेवानिवृत होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों 30 अप्रैल तक नौकरी जारी रखने की मंजूरी दी है। वहीं एनडीएमसी ने वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांगों को भी तीन माह की पेंशन जारी कर दी है। (जासं)

दिल्ली दंगे में जामिया का छात्र गिरफ्तार

नई दिल्ली : राजधानी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक और छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपित छात्र सफोरा जंगार जामिया से एमफिल कर रह है। छात्र को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके बाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने जामिया से पीएचडी कर रहे छात्र मीरान हैदर को दंगे की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया था। 24 और 25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 50 से अधिक लोगों की जान गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने दंगा फैलाने और इसमें शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सबसे सुर्खियों में रहा नाम आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन का है। वह फिलहाल जेल में बंद हैं। (जासं)

ऑनलाइन शिक्षण के लिए जामिया में दिया गया प्रशिक्षण

नई दिल्ली : ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के मद्देनजर शिक्षकों को इसके अनुकूल पढ़ाने के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआइ) की तरफ से ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया का रहा है। इसके तहत शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के दौरान जामिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इंटरनेट पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें 200 शिक्षकों के साथ जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर भी शामिल हुई। लॉकडाउन ले दौरान ऑनलाइन शिक्षण को काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है। (जासं)

निजामुद्दीन के बाद दिल्ली-6 बना बड़ा हॉटस्पॉट

चिंताजनक ▶ यहां अब तक 57 जमाती मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, इनमें 52 चांदनी महल की मस्जिदों से निकाले गए

कई इलाकों में सड़कों व गलियों में पुलिस व पैरा मिलिट्री की संख्या बढ़ाई

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

निजामुद्दीन के तब्लीगी मरकज से निकाले गए जमातियों की वजह से कोरोना के संक्रमण से जूझ रही दिल्ली में अब नया हॉट स्पॉट दिल्ली-6 बन गया है। निजामुद्दीन के बाद यह दूसरा ऐसा इलाका है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं। दिल्ली-6 में अब तक 57 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें 52 चांदनी महल की मस्जिदों से निकाले गए भी शामिल हैं। इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार देर रात ही सील कर दिया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक 13-15 मार्च के बीच तब्लीगी मरकज में हुए विशेष आयोजन के लिए विश्व के कई देशों व भारत के कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोग निजामुद्दीन आए थे। यहां जो लोग पहले आए उन्हीं को मरकज में जगह मिली थी। देर से आने वाले जमाती दिल्ली की अलग-अलग मस्जिदों व अपने परिचितों के घरों में ठहर गए। 28 मार्च को मरकज में ठहरे 2300 लोगों को पुलिस व जिला प्रशासन ने भले ही निकालकर क्वारंटाइन कर दिया, लेकिन जो लोग दिल्ली की मस्जिदों व घरों में ठहरे थे, उनका पता नहीं लग सका।

दिल्ली-6 के चांदनी महल थाना क्षेत्र में 77 छोटी-बड़ी मस्जिदें हैं। इनकी जांच में 13 मस्जिदों में छिपे 185 लोगों को एक सप्ताह पूर्व पुलिस ने ढूंढ़ निकाला था। इसमें 120 पुरुष व 18 महिलाएं विदेशी, जबकि 47 पुरुष व छह महिलाएं भारतीय शामिल थीं। इन लोगों की जांच कराई गई तो 52 लोग पॉजिटिव पाए गए। जामा मस्जिद में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। क्षेत्र में 24 मस्जिद हैं।

पहाड़गंज, नबी करीम व देशबंधु गुप्ता रोड थानाक्षेत्र में करीब 15 मस्जिद हैं। इन तीनों थानाक्षेत्र में नबी करीम में तीन, पहाड़गंज व देशबंधु गुप्ता रोड में एक-एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देशबंधु गुप्ता रोड थाना के तीन पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले वजीराबाद, सराय रोहिल्ला व सदरबाजार की मस्जिदों से पुलिस ने 15 जमातियों को क्वारंटाइन किया था।

कोरोना वायरस के चलते चांदनी महल को सील कर दिया गया है। यहां जाने वाले मार्ग पर लगाए गए बेरीकेट पर संक्रमण रोधी दवा का छिड़काव करता निगम कर्मी। जागरण

चार थानाक्षेत्र के 29 इलाके सील

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दरियागंज, चांदनी महल, हौजकाजी व जामा मस्जिद थानाक्षेत्र के 29 इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इन इलाकों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जिन इलाकों को सील किया गया है, उनमें दिल्ली गेट, रकाबगंज, तुर्कमान गेट, हज मंजिल, वर्धमान प्लाजा, डीडीए फ्लैट्स इंट्री, शंकर गली, फाटक तालियान गली, गली सुशीला, गली अकीला टी प्वाइंट, प्रेम नारायण चौक, प्रेम नारायण कट, टी प्वाइंट चौरी वालान, चौरी वालान रोड, चौरी वालान चौक, मटिया महल चौक, चितली कवर चौक, हवेली आजम खान कट-सरावती नेहरी वाला, सुभाष मोहल्ला, पटौदी हाउस, कूचा दखानी राय, सब्जीमंडी रोड, सर सैयद मार्ग नियर सबरवाल हॉस्पिटल, तिराहा भैरुम खान, कूचा तारा चांद कट-दाई वाली मस्जिद, लाल गली नंबर एक व दो व गली बालियान शामिल है।

दिल्ली-6 में छिपे हो सकते हैं और जमाती : पुलिस को शक है कि दिल्ली 6 में अभी और जमाती छिपे हुए हैं। इसे देखते हुए पुलिस लगातार मस्जिदों व मदरसों की जांच कर रही है।

स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि यदि उनकी जानकारी में कहीं जमाती हैं, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस इस क्षेत्र की ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। इससे जहां भीड़ होगी तत्काल पता चल जाएगा। वहीं घरों की चेकिंग भी की जा रही है। इधर उत्तर-पूर्वी जिला, जामिया नगर व शाहीन बाग के इलाके में भी कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस व पैरा मिलिट्री की संख्या बढ़ाई : दिल्ली-6 के कई इलाकों में सड़कों व गलियों में पुलिस व पैरा मिलिट्री की संख्या बढ़ा दी गई है। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों के साथ सख्ती से निपटें। लापरवाह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके वाहनों को तुरंत जब्त कर लें। शुक्रवार व शनिवार को इस मसले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों की बार-बार बैठकें भी होती रहीं।

सीजन का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में शनिवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को रविवार को बादल छाए रहने के साथ 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की उम्मीद जताई है, जबकि सोमवार को बारिश की उम्मीद है। शनिवार को दिनभर मौसम साफ रहा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली।

मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग में शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस ज्यादा 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री ज्यादा 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है। अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इससे पहले अधिकतम तापमान पांच अप्रैल को पालम में 37.5 डिग्री सेल्सियस और सफदरजंग में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। उसके बाद शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

हवा में नमी का अधिकतम स्तर 78 फीसद और न्यूनतम स्तर 30 फीसद रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है।

प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के प्रमुख डॉ. कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय हो रहा है। इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में रविवार को पड़ेगा। वहीं दिल्ली-एनसीआर में इसका असर सोमवार की शाम से होगा। इस वजह से बारिश होगी। स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत ने बताया कि अब गर्मी बढ़ने लगी है।

सफदरजंग में कोरोना से आयुर्वेद डॉक्टर की मौत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

सफदरजंग अस्पताल में कोरोना से पीड़ित आयुर्वेद के 58 वर्षीय डॉक्टर की शुक्रवार देर रात मौत हो गई। वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। अस्पताल प्रशासन ने उनकी मौत की पुष्टि की है। सफदरजंग में कोरोना से यह पहली मौत है। उनकी पत्नी व बेटा भी संदिग्ध हैं। वे भी अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

डॉक्टर को 8 अप्रैल को बुलंदशहर के एक अस्पताल से सफदरजंग में रेफर किया गया था। उस वक्त ही उनकी हालत बेहद गंभीर थी। यहां जांच के दौरान उनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। सफदरजंग अस्पताल को कोरोना के इलाज के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है। इस अस्पताल से अब तक कोरोना के 38 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। इसमें दिल्ली के अलावा आगरा व एनसीआर के मरीज शामिल हैं। फिलहाल इस अस्पताल में कोरोना के 24 मरीज भर्ती हैं।

लोकनायक में नर्स संक्रमित : दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। शनिवार को लोकनायक अस्पताल की एक नर्स भी संक्रमित पाई गई। इस तरह दिल्ली में अब तक आठ अस्पतालों के करीब 40 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से पीड़ित मिल चुके हैं। हालांकि लोकनायक का यह पहला मामला सामने आया है। पीड़ित नर्स सहायक नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। ड्यूटी रोस्टर से संबंधित दायित्व उनके पास है। इस अस्पताल में दो और सहायक नर्सिंग अधिकारी संदिग्ध हैं, जिनकी रिपोर्ट रविवार को आ सकती है। ऐसे में अस्पताल के कई अन्य कर्मचारी क्वारंटाइन किए जा सकते हैं। दिल्ली में अब तक दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान, एम्स, सफदरजंग, सरदार पटेल अस्पताल, डीडीयू, गंगाराम सहित आठ अस्पतालों व मोहल्ला क्लीनिकों के कर्मचारी चपेट में आ चुके हैं। इनमें कई डॉक्टर शामिल हैं।

अगले आदेश तक दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान बंद

जासं, नई दिल्ली : दिलशाद गार्डन स्थित दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। यहां भर्ती मरीजों को न्यू अशोक नगर स्थित धर्मशिला नारायणा अस्पताल भेज दिया गया है। वहां उनका इलाज सरकार के खर्चे पर हो रहा है। शनिवार को यहां कोई पॉजिटिव मामला नहीं आया। अब तक यहां डॉक्टर, मरीज व नर्सिंग स्टाफ सहित कुल 25 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें एक कैंसर मरीज की मौत भी हो चुकी है।

शुक्रवार से कैंसर संस्थान में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें चार-पांच दिन का समय लग सकता है। इसकी वजह से कैंसर के मरीजों को परेशानी आ रही है। शास्त्री पार्क निवासी मोहम्मद करीम का यहां नवंबर से इलाज चल रहा है। पिछले 15 दिन से वह पत्नी के साथ यहां चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें मना कर दिया जा रहा है। इसी तरह की दिक्कतें और भी मरीजों को आ रही है। इस पर कैंसर संस्थान प्रशासन का कहना है कि ऐसे मरीजों की व्यवस्था धर्मशिला नारायणा अस्पताल में की जाएगी। इसके लिए उन्हें कैंसर संस्थान से एक पत्र लिखवाना होगा।

पीएसवी चालकों को मिलेंगे पांच-पांच हजार रुपये

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक मदद वाहन के परमिट होल्डर को नहीं, वाहन चालकों को ही मिलेगी। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को वित्तीय मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत पीएसवी (पब्लिक सेवा व्हीकल्स) चालकों को पांच-पांच हजार रुपये की एकमुश्त राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार से यह आर्थिक मदद सिर्फ एक बार दी जा रही है। इसका लाभ 2 लाख 70 चालकों को मिलेगा।

इस राशि का लाभ ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित चालकों को मिलेगा। इसके लिए पात्र चालकों को दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और 27 अप्रैल तक जारी रहेगी।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश

कैलाश गहलोत। (फाइल)

गहलोत ने कहा कि सरकार पब्लिक सेवा वाहन जैसे ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी के चालक लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी के शिकार हैं। इनकी मदद करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यह वित्तीय मदद की प्रक्रिया त्वरित होगी और राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी राशि : सरकार का कहना है कि आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं पीएसवी धारकों को मिलेगा, जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होगा। पात्र लाभार्थी को फार्म भरने के दौरान पीएसवी बैज संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंग और बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर की जानकारी देनी आनिवार्य है। सरकार ने किसी तरह की

दिल्ली सरकार को रैपिड टेस्टिंग किट का इंतजार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर टेस्टिंग की रणनीति तैयार की है। मगर केंद्र से अभी तक रैपिड किट नही मिल सकी हैं। दिल्ली सरकार ने एक लाख रैपिड किट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जैन ने ट्वीट कर कहा कि हमें 13,500 पीपीई किट केंद्र सरकार से मिल रही हैं, जो कि अभी अंडर ट्रांसफर हैं। स्कैनिंग के लिए हमने हर जगह पर 50 टीमें, 100 टीमें, 150 टीमें बनाई हैं और एक-एक जगह को स्कैन कर रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग किट अभी नहीं पहुंची है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई है।

पूछताछ करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्प लाइन नंबर 011-23930763 और 011-23970290 है। इन नंबरों पर रविवार को छोड़कर अन्य कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पूछताछ की जा सकेगी।

मास्क नहीं पहनने पर सौ के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

लॉकडाउन का पालन न करा पाने पर दो थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का ठीक तरीके से पालन न करा पाने से नाराज होकर पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने शनिवार को दो थानाध्यक्षों को लाइन हाजिर कर दिया है।

कोरोना को लेकर पुलिस द्वारा की जा रही सख्ती के बीच पुलिस आयुक्त द्वारा की गई यह पहली कार्रवाई है। मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक जिन थानाध्यक्षों को लाइनहाजिर किया गया है, उनमें अमर कॉलोनी का थानाध्यक्ष अनंत गुंजन व बाड़ा हिंदू राव के थानाध्यक्ष का नाम योगेश मल्होत्रा है। इनके इलाके में लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कराया जा रहा था। रेहड़ी वाले खुलेआम सड़कों व गलियों में इकट्ठा होकर सब्जियां बेच रहे थे। दुकानों पर लोगों की भीड़ थी। लोग शारीरिक दूरियां आदि नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर आला अधिकारियों को भेज दी थी। जिसके आधार पर आयुक्त ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की।

लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्य से घर से बिना मास्क निकले सौ लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस ने 3515 लोगों को हिरासत में लिया। ये वे लोग थे, जो बिना किसी जायज कारण के घर से बाहर सड़कों पर निकल आए थे। पुलिस पूछताछ में इनके पास घर से बाहर निकलने का कोई सही कारण नहीं मिलने पर इन्हें हिरासत में लिया गया।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जन संपर्क अधिकारी एसीपी अनिल मित्तल के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से निकलने की मनाही है। सिर्फ आवश्यक कार्य के चलते ही लोगों को मूवमेंट पास के जरिये बाहर निकलने की अनुमति है। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को परिचय पत्र के साथ निकलने की अनुमति है। इन्हें भी मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना किसी कारण घर से निकलने पर लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में शनिवार को पुलिस ने 200 एफआइआर भी दर्ज कीं। इसके अलावा बिना वजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों में से 400 लोगों के वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया।

निजी मुचलके पर ही कैदियों को किया जाए रिहा : हाई कोर्ट

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली राज्य विधिक प्राधिकरण द्वारा कैदियों को बिना जमानतदार ही रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षकों को अहम निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ व न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में जमानती नहीं देने पर जमानत पाए कैदियों को निजी मुचलके पर ही रिहा किया जाए। पीठ ने कहा कि मुचलका जेल अधीक्षक के अनुसार तय होगा। दिल्ली राज्य विधिक प्राधिकरण की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि कई विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिए गए हैं। जमानतदार नहीं लाने के कारण कई कैदी जेल से बाहर नहीं जा सकते। ऐसे में कैदियों को बिना जमानतदार के ही रिहा करने का आदेश दिया जाए।

निगमबोध घाट के पास तीन रैन बसेरों में बेघरों ने लगाई आग

निगम बोध घाट के पास बेघरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सौ. सुधी पाठक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने बाहरी लोगों को खाने-पीने का सामान बांटने से रोका तो गुस्साए बेघरों ने शनिवार शाम को तीन रैन बसेरों में आग लगा दी। ये लोग इन्हीं रैन बसेरों में रहते भी थे। कश्मीरी गेट इलाके में निगमबोध घाट के पास स्थित इन रैन बसेरों में आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी उन्होंने पथराव किया और पुलिस जिप्सी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर, पुलिस का कहना है कि बेघरों को रैन बसेरों में मिल रहा भोजन रास नहीं आ रहा था। ये लोग लॉकडाउन में बाहरी लोगों द्वारा बांटे जा रहे फास्ट-फूड व अन्य व्यंजनों की मांग कर रहे थे। पुलिस ने छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, बाहरी खाने पर रोक के बाद शुक्रवार को भी सिविल डिफेंस कर्मियों के साथ इन बेघरों ने झगड़ा व मारपीट की थी। उसके बाद छह बेघर पास स्थित यमुना नदी में कूद गए थे और फिर बाहर निकल आए। शनिवार दोपहर नदी से एक बहती हुई लाश को इन बेघरों ने निकाला और उसे अपना साथी बताते हुए हंगामा करने लगे और वहां मौजूद सिविल डिफेंस कर्मियों से झगड़ने लगे।

मध्य रेंज के संयुक्त आयुक्त सुभाशीष चौधरी का कहना है कि यमुना में मिली लाश निगमबोध घाट के रैन बसेरे में रहने वाले बेघर की नहीं है। लाश पीछे से पानी में बहकर आई है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सब्जीमंडी मोर्चरी में रखवा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थित साफ हो पाएगी।

रैन बसेरों में क्षमता से ज्यादा लोग : निगमबोध घाट के पास यमुना किनारे कई रैन बसेरे हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में बेघर रहते हैं। पुलिस का कहना है कि रैन बसेरों में रहने की जितनी क्षमता हे उससे काफी ज्यादा बेघर वहां रहते हैं। ये लोग पहले रैन बसेरों में मिलने वाले खाना पर निर्भर थे। लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में अमीर लोगों ने यहां आकर बेघरों को चिप्स, कोलड्रिंक, बर्गर, पूरी-सब्जी आदि बांटना शुरू कर दिया था। मंदिरों से भी इन्हें खाने-पीने का सामान बांटे जाने लगे। जिससे इन्होंने रैन बसेरे में मिलने वाला दाल-चावल व दलिया आदि खाना छोड़ दिया था।

ट्रायल

कोरोना के इलाज में एचसीक्यू के ज्यादा प्रभावी होने की उम्मीद, इनहेलर से दवा सीधे फेफड़े में पहुंचकर दिखाती है असर

इनहेलर-नेबुलाइजर से करोनो को चित करने की तैयारी

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

कोरोना के इलाज के लिए अभी तक कोई प्रमाणित दवा नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) से चिकित्सा जगत की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए दुनिया भर में इस दवा की मांग भी बढ़ी है। यहां भी मरीजों को क्लीनिकल ट्रायल के रूप में यह दवा दी जाने लगी है। एम्स भी कोरोना के इलाज में इस दवा का ट्रायल कर रहा है। इसके साथ ही इस दवा का इनहेलर व नेबुलाइजर विकसित करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इसके माध्यम से दवा आसानी से सीधे फेफड़े तक पहुंच सकेगी। एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह अभी शोध के स्तर पर है।

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुछ ऐसे अध्ययन आए हैं, जिनमें यह पाया गया है कि मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का इस्तेमाल सुरक्षित है। यह कोरोना के इलाज में काम भी कर रही है। इसलिए यहां भी ट्रायल के रूप में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। साथ ही उसका डाटा एकत्रित किया जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि यह इलाज में कितना प्रभावी है।

साथ ही नैनो तकनीक आधारित हाइड्रोक्लोरोक्वीन की ऐसी दवा बनाने पर भी शोध चल रहा है। इसके पीछे कोशिश यह है कि नैनो पार्टिकल के माध्यम से दवा को सीधे फेफड़े में पहुंचाया जाए।

यह देखा गया है कि सांस की बीमारियों में इनहेलर व नेबुलाइजर के रूप में ली जाने वाली दवाएं ज्यादा असरदार होती हैं। कोरोना वायरस भी फेफड़े पर अटैक करता है। इस वजह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इनहेलर तैयार करने की कोशिश की जा रही है।

फाइल फोटो

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का दो तरह से इस्तेमाल

डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इस दवा का दो तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो स्वास्थ्य कर्मियों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफाइल एक्सिस (बीमारी से पहले बचाव के लिए दी जाने वाली दवा) के रूप में दी जा रहा है ताकि यदि इलाज के दौरान उनमें थोड़ा भी संक्रमण है तो वह ठीक हो सकें।

दूसरा ऐसे मरीजों को दिया जा रहा है जिनमें बीमारी के लक्षण हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है या आइसीयू में हैं। उन्हें पांच दिन के लिए यह दवा देकर देखा जा रहा है कि उन पर क्या असर पड़ा। उल्लेखनीय है कि फ्रांस में कोरोना के मरीजों पर इस दवा का परीक्षण किया गया है। इस दवा को असरदार बताया गया है, लेकिन अध्ययन में कम मरीजों के शामिल होने के कारण अभी इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है।

10 मार्च को कर्नाटक में कोरोना से पहली मौत हुई थी। इसके बाद देश में भले ही एक महीने के अंदर कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या दो सौ को पार कर गई है, लेकिन अभी भी यहां इस महामारी से मरने वालों की दर यूरोप, अमेरिका और अन्य विकसित देशों की तुलना में लगभग तीन फीसद कम है।

लॉकडाउन और शारीरिक दूरी ही सबसे बेहतर उपाय : हर्षवर्धन

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत की विशाल आबादी को देखते हुए कोरोना की जांच के काम का दायरा इस तरह से बढ़ाया जाए कि इसमें निरंतरता बनी रहे। वैसे इस बीमारी से पार पाने में लॉकडाउन और उचित शारीरिक दूरी रखना ही सबसे बेहतर उपाय है। यह बात शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कही।

एक पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में स्वास्थ्य मंत्री ने देश में जरूरत से कम लोगों की कोरोना जांच होने की बात को खारिज करते हुए कहा कि हम उन लोगों की जांच पहले कर रहे हैं जिनमें इस बीमारी के लक्षण हैं या जिन लोगों के इस बीमारी की चपेट में आने का खतरा अधिक है।

जल्द ही 48,538 वेंटीलेटर और उपलब्ध कराएंगे : देश में वेंटीलेटर की कमी के संबंध में किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संक्रमित हुए लोगों में 80 फीसद लोगों में इसका प्रभाव बहुत मामूली है या उनमें इसके लक्षण ही नहीं मिलते। 15 फीसद लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। बाकी पांच फीसद ही इतने गंभीर होते हैं जिन्हें वेंटीलेटर की जरूरत पड़ती है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों के लिए 17,000 वेंटीलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में हम 48,538 वेंटीलेटर और उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

देश में पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) किट की उपलब्धता के बारे में उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर इसका उत्पादन न होने के कारण इसकी किल्लत है। हम लोग 1.57 करोड़ किट का इंतजाम करवा रहे हैं। देश में कोरोना की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि 80 फीसद मामले 17 राज्यों के 71 जिलों में सामने आए।

दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोग जितना अनुशासित होकर इस बारे में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे उतनी जल्दी ही यह बीमारी काबू में आएगी। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए समाज को शारीरिक दूरी, क्वारंटाइन और बिना लक्षण वाले लोगों को अलग-थलग करने

बोले स्वास्थ्य मंत्री

- जांच कार्य में निरंतरता जरूरी, पीपीई किट व वेंटीलेटर का प्रबंध करेंगे
- कोरोना से निपटने में राज्य भी कर रहे हैं काफी अच्छा काम

हर्षवर्धन। फाइल

के प्रयासों में अपनी भूमिका निभानी होगी। हमारे प्रयास में जरा सी खामी रहने के बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे।

लॉकडाउन व शारीरिक दूरी सबसे अच्छी 'सोशल वैक्सीन' : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत समेत सभी देश इस समय कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। मेरा मानना है मौजूदा समय में शारीरिक दूरी और लॉकडाउन सबसे अच्छी 'सोशल वैक्सीन' है। मैंने इन दोनों उपायों को सोशल वैक्सीन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों न केवल इस बीमारी को फैलने से रोक रहे हैं बल्कि उसका असर भी खत्म कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिन भारत के लिए बहुत अहम हैं। दुनिया के और देशों जहां लॉकडाउन जैसे उपाय कड़ाई से लागू हैं वहां भी कोरोना संक्रमितों के मामले इस तरह बढ़ रहे हैं कि इनका ग्राफ दो से चार सप्ताह में ही वक्राकार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि चिह्नित किए हाटस्पॉट की जिम्मेदारी समाज को भी लेनी होगी ताकि वहां शारीरिक दूरी जैसे उपायों पर सख्ती से अमल कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में 15 से ज्यादा मामले सामने आए हैं वहां के लिए हमने विशेष कार्ययोजना बनाई है। वहीं 15 से कम मामले वाले 76 जिलों में समूह बनाकर संक्रमण को नियंत्रित करने की योजना लागू की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे सभी केंद्र के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने तो काफी उल्लेखनीय काम किया है।

उन्होंने सरकार के जांच संबंधी उपायों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत की विशाल आबादी को देखते हुए जांच का दायरा इस तरह बढ़ाना होगा कि उसमें निरंतरता बनी रहे। उन्होंने बताया कि अभी 136 सरकारी लैब और 59 अधिकृत लैब में जांच हो रही है। हमारी कोशिश है कि जांच सुरक्षित तरीके से हो और उसके परिणाम सही हों।

उन्होंने कहा कि इस बात की आशंका है कि आगे चलकर कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा पैटर्न पर मौसमी फ्लू के वायरस के साथ घालमेल कर ले। लेकिन अभी जो बात सबसे जरूरी है कि हम लोगों को मौतों को सीमित करना है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा।

बंगाल में लॉकडाउन उल्लंघन पर गृह मंत्रालय ने जताया एतराज

नई दिल्ली, प्रेट्र : बंगाल में लॉकडाउन को धीरे-धीरे कमजोर किए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपत्ति व्यक्त की है। मंत्रालय का कहना है कि राज्य में गैरजरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के साथ-साथ पुलिस ने धार्मिक जमावड़ों की भी मंजूरी प्रदान कर दी।

बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता में राजाबाजार, नर्केल डांगा, तोपसिया, मेटियाबुर्ज, गार्डेनरीच, इकबालपुर और मानिकतला के सब्जी, मछली और मटन बाजारों में शारीरिक दूरी मानकों का पूर्ण उल्लंघन कर लोग जमा हो रहे हैं। जबकि नर्केल डांगा जैसे इलाकों में कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।

पत्र के मुताबिक, 'यह भी रिपोर्ट मिली है कि पुलिस धार्मिक जमावड़ों को भी अनुमति दे रही है। मुफ्त राशन संस्थागत आपूर्ति प्रणाली के बजाय राजनीतिक नेताओं द्वारा वितरित किया जा रहा है। हो सकता है कि इससे कोविड-19 संक्रमण का प्रसार हुआ हो।' मंत्रालय का कहना है कि ऐसी गतिविधियां आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का उल्लंघन है और इसके लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

मुख्यमंत्री राहत कोष में सीएसआर फंड चाहते हैं राज्य

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश भर में पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या के कारण कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष लंबा खिंचने की आशंका को देखते हुए राज्यों से कारपोरेट सीएसआर फंड मुख्यमंत्री राहत कोष या कोविड-19 के लिए राज्य राहत कोष में भी भेजे जाने की मांग उठ रही है। सूत्रों ने कहा कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को राज्य सरकारों समेत विभिन्न भागीदारों से प्रतिवेदन मिले हैं। सीएम राहत कोष में कारपोरेट अंशदान को भी कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबलिटी (सीएसआर) पर खर्च के रूप में शामिल करने की मांग की गई है। अभी तक उनकी मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

दो हफ्ते बाद पता चलेगा कितनी कारगर है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन

इंतजार ▶ कोरोना को रोकने में इसके प्रभाव का अध्ययन कर रहा आइसीएमआर

कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में ही मिल सकता है इस दवा का लाभ

नीलू रंजन, नई दिल्ली

दुनियाभर के देशों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हासिल करने की होड़ लगी है और भारत के पास लगातार इसके लिए अनुरोध आ रहे हैं। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना को रोकने में कितनी कारगर है यह साबित होने में 15 दिन और लग सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर के अनुसार इस पर अध्ययन चल रहा है और निश्चित तौर पर कुछ भी कहने में दो हफ्ते और लग जाएंगे।

दरअसल, आइसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के पास रहने वालों और इलाज करने वाले डॉक्टरों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा कोरोना से संक्रमण के लिए बचाव के रूप में दी

डॉ. रमन गंगाखेड़कर। फाइल

जा रही है। डॉक्टर गंगाखेड़कर ने कहा कि यह दवा कोरोना से बचाव में कितनी सक्षम है, इसका पता लंबे समय तक निगरानी के बाद लग सकता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को यह दवा दी जा रही है, उनकी आइसीएमआर पूरी निगरानी कर रहा है और दो हफ्ते तक और निगरानी के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।

डॉक्टर गंगाखेड़कर ने कहा कि जैसे ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के कोरोना वायरस को रोकने में प्रभावी होने की पुष्टि हो जाएगी, आइसीएमआर खुद ही आम लोगों के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस जारी कर देगा। इस दवा के फिलहाल आम जनता के उपयोग पर रोक लगाने के बारे में पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसा दो-तीन कारणों से किया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह दवा कितनी कारगर है इसका पता लगाया जाना अभी बाकी है। दूसरे इस दवा के साइड इफेक्ट होते हैं और दिल के मरीजों के लिए यह घातक हो सकती है। कोरोना के भय के कारण घबराहट में इसके इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में नहीं पहुंचा है इसलिए सबके इससे प्रभावित होने की आशंका कम है। वहीं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तभी तक प्रभावी रह सकती है जब तक कोई व्यक्ति इसे निश्चित अंतराल पर लेता रहता है। आठ हफ्ते के बाद दुनिया में कहीं भी इस दवा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे में यदि कोरोना वायरस का आउटब्रेक डेढ़ या दो महीने बाद हुआ और उस समय सबको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने की जरूरत समझी गई तो अधिकांश को यह इसलिए नहीं दी जा सकेगी क्योंकि वे इसका इस्तेमाल पहले ही कर चुके होंगे। यही कारण है कि सरकार ने इसकी खुली बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है।

कैट ने कहा, वीडियो कांफ्रेंस से सुनवाई में पेश आ रही है कठिनाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : वीडियो कांफ्रेंस के बुनियादी ढांचे के अभाव में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) को लॉकडाउन के दौरान सुनवाई करने में कठिनाई पेश आ रही है। कैट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा से जुड़े मामलों का निपटारा करता है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, लॉकडाउन लागू होने के बाद ट्रिब्यूनल की पीठों के लिए काम करना असंभव हो गया है क्योंकि न तो वकील और न ही कैट के कर्मचारी इस स्थिति में हैं कि वे काम पर आ सकें। बयान के मुताबिक, 'वीडियो कांफ्रेंस से सुनवाई करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है क्योंकि पहले तो आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं और दूसरा लॉकडाउन की वजह से इन्हें खरीदना भी संभव नहीं है।' बयान में कहा गया है कि कैट की मुख्य पीठ और देशभर में इसकी पीठों की हमेशा यही कोशिश रही है कि जितने ज्यादा हो सकें उतने मामले निपटाए जाएं और ट्रिब्यूनल से संपर्क करने वाले व्यक्तियों की संतुष्टि के लिए काम किया जाए। वास्तव में फरवरी माह तक मामलों के निपटारे की दर अभूतपूर्व रही है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करके सुनवाई की जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद यह असंभव हो गई।

अमेरिका में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ सोमवार को मामले में सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

अमेरिका में गंभीर रूप से फैली कोरोना महामारी को देखते हुए अमेरिका में फंसे भारतीयों को विशेष विमान से भारत वापस लाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है। वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा ने जनहित याचिका दाखिल कर अमेरिका में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मांग की है। शीर्ष अदालत सोमवार को इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली है। अमेरिका में यह गंभीर रूप से फैली है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जारी लॉकडाउन के चलते सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं जिससे अमेरिका में रहने वाले भारतीय वहां फंस गए हैं। वे भारत नहीं आ सकते। मखीजा ने कोर्ट से भारत सरकार को अमेरिका में अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को विशेष विमान से भारत लाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार को अमेरिका में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए उचित कदम उठाने को कहा जाए।

इस याचिका के अलावा केरल के एक कांग्रेस सांसद एमके राघवन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कोरोना

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

महामारी के चलते केंद्र सरकार को खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित वापस लाने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार विशेष उड़ानों की इजाजत दे, क्योंकि खाड़ी देशों में फंसे बहुत से लोग अपने पैसे से भारत आना चाहते हैं। साथ ही कहा गया है कि सरकार सुनिश्चित करे कि वहां जो लोग फंसे हैं उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधाएं मिलें।

याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का काम है। इसलिए उसे इस संदर्भ में जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए ताकि वक्त रहते दूसरे देशों में फंसे लोगों की जान बचाई जा सके।

अमेरिका से भारतीयों के एच-1बी वीजा अवधि बढ़ाने का आग्रह

नई दिल्ली, आइएएनएस : कोरोना महामारी खत्म होने तक भारत ने अपने नागरिकों के एच-1बी और अन्य वीजा अवधि बढ़ाने का अमेरिका से आग्रह किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, नई दिल्ली ने यह अनुरोध वाशिंगटन से तब किया, जब उसे यह जानकारी मिली कि अमेरिकी सरकार ने कंपनियों से एच-1बी वीजा वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने को कहा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने अमेरिकी विदेश उप मंत्री स्टीफन बेगन के सामने यह मुद्दा उठाया। लगभग तीन लाख भारतीय एच-1बी वीजा पर अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। अगर उनकी वर्तमान कंपनी उन्हें काम से निकाल देती है तो उन्हें अपना एच-1बी वीजा बनाए रखने केलिए 60 दिनों के अंदर दूसरी नौकरी खोजनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें वापस भारत आना पड़ेगा। दरअसल, एच-1बी एक गैर प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को कुछ खास व्यवसायों में काम पर रखने की अनुमति देता है। वर्तमान संघीय नियमों के मुताबिक, नौकरी छोड़ने के 60 दिनों के भीतर इन वीजाधारकों को अपने परिवार के साथ अमेरिका छोड़ना जरूरी है।

सड़क हादसों, मौतों पर लगा ब्रेक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भारत में रोजाना सड़क हादसों में मरते हैं 414 लोग, लॉकडाउन से पूरे एक महीने में हुई 239 मौतें
- कोरोना ने अन्य दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों पर भी लगाया अंकुश, दुनियाभर में यही रुख

कोरोना भले ही घातक महामारी हो, लेकिन भारत में इससे उतनी मौतें नहीं हो रहीं, जितनी रोजाना सड़क या दूसरे हादसों में होती हैं। पर्यावरण में सुधार के अलावा कोरोना की इस मुसीबत में कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। उदाहरण के लिए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप भारत समेत दुनियाभर में सड़क हादसों तथा उनसे होने वाली मौतों की संख्या नगण्य हो गई है।

कोरोना के कारण दुनियाभर में ज्यादातर लोग घरों में बंद हैं। उत्पादक गतिविधियां न के बराबर रह गई हैं। वाहनों की आवाजाही भी अत्यंत सीमित हो गई है। इसका सकारात्मक असर सड़क सुरक्षा पर पड़ा है तथा भारत ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर कोरोना ग्रस्त देशों में सड़क हादसों का ग्राफ नगण्य हो गया है। इससे भारत में रोजाना 1,279 सड़क हादसे नहीं होने से 414 लोगों की जान बच रही है। वैश्विक स्तर पर भी सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन मरने वाले 3,700 लोग काल के गाल में समाने से बच रहे हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत में हर साल साढ़े चार लाख से अधिक सड़क हादसों में तकरीबन डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं। वर्ष 2018 में 4,67,044 सड़क दुर्घटनाओं में 1,51,417 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दैनिक आधार पर यह आंकड़ा 1,279 सड़क हादसों और 414 मौतों का बनता है। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में सालाना तकरीबन 13.5 लाख मौतों के हिसाब से हर रोज 3,700 लोगों की मृत्यु होती है।

कोरोना से कई गुना घातक हैं सड़क हादसे : सड़क हादसों के मुकाबले कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं। भारत में नौ मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक कुल मिलाकर 239 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इसका दैनिक औसत आठ से भी कम मौतों का निकलता है जो सड़क हादसों में होने वाली दैनिक मौतों का महज 51वां हिस्सा है।

वैश्विक स्तर पर भी देखें तो कोरोना से होने वाली मौतें सड़क हादसों के मुकाबले कम हैं। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 11 अप्रैल की सुबह तक कोरोना से कुल 92,941 मौतें हुई थीं। 11 जनवरी को चीन में कोरोना से हुई पहली घोषित मौत के बाद अब तक के तीन महीनों में हुई उक्त मौतों के हिसाब से कोरोना से होने वाली दैनिक मौतों का आंकड़ा 1032 बैठता है जो सड़क हादसों से होने वाली दैनिक 3700 मौतों के मुकाबले एक तिहाई से भी कम है।

दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा, भारत के लिए नहीं : कोविड-19 एक प्राकृतिक वायरस है अथवा इसे चीन में मनुष्य द्वारा जैविक हथियार के तौर पर विकसित किया गया है, यह तो अभी जांच का विषय है। लेकिन यदि इसे प्राकृतिक आपदा माना जाए तो वैश्विक स्तर पर अवश्य इसे अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। परंतु भारत में कोरोना तब भी पीछे रहेगा। क्योंकि भारत में हर साल औसतन करीब 7 हजार लोगों की प्राकृतिक आपदाओं में मौत होती है। वर्ष 2018 में यहां 6,891 लोग प्राकृतिक आपदाओं में मार गए थे। वहीं दूसरी ओर कोरोना के कारण यहां एक महीने में महज 258 मौतों के हिसाब से (यदि कोरोना से मौतों की वृद्धि दर और नहीं बढ़ती है) सालाना आंकड़ा भी मात्र 3,098 मौतों का बनता है। यह प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों के आधे से भी कम है।

झारखंड को तत्काल मदद करे केंद्र सरकार : हेमंत

राज्य ब्यूरो, रांची

- मुख्यमंत्री ने फिर मांगी मदद, राज्य की हालत का दिया हवाला
- बढ़ रहे संक्रमण से निपटने के लिए चाहिए जरूरी संसाधन

झारखंड ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक मदद तुरंत उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में लगतार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जहां चिंतित हैं, वहीं देश के अन्य राज्यों में फंसे लगभग सात लाख झारखंड के लोगों को राहत पहुंचाना भी मुश्किल टास्क है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी उन्होंने इन परेशानियों को साझा करते हुए पीएम से मदद की गुहार लगाई। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कई बार केंद्र से मदद की गुहार लगा चुके हैं। दोनों नेता केंद्र पर झारखंड की उपेक्षा का भी आरोप लगा चुके हैं। वहीं, खजाने की खस्ता हालत के बारे में भी जानकारी दे चुके हैं। यह शिकायत भी जाहिर की कई बार की मांग के बाद भी झारखंड को जरूरी संसाधन मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं।

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन को बढ़ाने अथवा समाप्त करने को लेकर अपनी ओर से कोई राय नहीं दी और इस फैसले को केंद्र के निर्णय पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसके खिलाफ रणनीति और लॉकडाउन के मुद्दे पर शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। रांची से कांफ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी बात रखी। एएनआइ

कि इस फैसले पर झारखंड केंद्र के निर्णय के साथ है।

जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर : झारखंड सरकार राज्य में कोरोना जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया है। फिलहाल सिर्फ दो जांच केंद्रों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिली है। आइसीएमआर ने रांची के इटकी में जांच की अनुमति यह कहते हुए नहीं दी कि एक ही जिला में दो लैब की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार का कहना है कि रांची से तीन जिले लोहरदगा, लातेहार तथा गुमला सटे हैं जिससे यहां के संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच इटकी में हो सकती है। पीएमसीएच, धनबाद में जांच की सारी तैयारी पूरी हो गई है, इसके बावजूद अभी तक केंद्र सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है।

पीपीई किट की कमी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि राज्य सरकार ने केंद्र से 75,500 पीपीई किट की मांग की थी, लेकिन अभी तक महज 9350 ही मिले हैं। इसी तरह, 26,700 जांच किट की मांग की गई थी जबकि राज्य को 4700 जांच किट ही मिले। राज्य सरकार ने एक सप्ताह पहले ही यह कहते हुए 10,000 जांच किट उपलब्ध कराने की मांग की थी कि राज्य के पास अब सिर्फ एक सप्ताह का ही कोटा बचा है। राज्य सरकार ने 300 थर्मल स्कैनर भी मांगे, लेकिन अभी तक 100 ही मिल पाए हैं। इसी तरह, राज्य सरकार ने कम से कम 100 वेंटीलेटर की भी मांग की है जो अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी संसाधन जल्द उपलब्ध नहीं कराए गए तो स्थिति को संभालने में दिक्कत होगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दो बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से इस संदर्भ में बात की है, जबकि स्वास्थ्य सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने दो बार आइसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव को पत्र लिखा है।

कब चलेगी रेल

आइआरसीटीसी यात्रियों से सुविधा शुल्क के नाम पर संकटकाल में भी वसूल रहा रुपये, 15 अप्रैल से ट्रेनें नहीं चलीं तो कट जाएंगे टिकट बुक कराने वालों के 15 से 30 रुपये

ऑनलाइन टिकट बेच 22 लाख रुपये प्रतिदिन कमा रहा रेलवे

हरिचरण यादव, भोपाल

कोरोना संकट के दौर में रेलवे टिकट बेचकर प्रति यात्री 15 या 30 रुपये (आरक्षण श्रेणी के मुताबिक) के हिसाब से प्रतिदिन करीब सवा लाख से ज्यादा यात्रियों से कमाई कर रहा है। ये रुपये सुविधा शुल्क के नाम पर लिए जा रहे हैं। वह भी तब जब 15 अप्रैल से ट्रेनों के संचालन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये टिकट इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) बेच रहा है, जो रेलवे का ही उपक्रम है। एक से दूसरी जगह जाने की उम्मीद में लोग भी सुविधा शुल्क देकर ऑनलाइन टिकट बुक करवा रहे हैं। यदि ट्रेनें नहीं चली तो इन्हें घर बैठे नुकसान होगा। जबकि, रेलवे और आइआरसीटीसी को फायदा होगा। इस सुविधा शुल्क के नाम पर देशभर से रेलवे प्रतिदिन करीब 22 लाख रुपये कमा रहा है।

रेलवे को तो ब्याज भी मिल रहा : रेलवे के पास यात्रियों द्वारा यात्रा पूर्व चुकाई जा रही किराये की करोड़ों की राशि है। यह राशि 14 अप्रैल की स्थिति तक उसके पास रहेगी। यदि ट्रेनें चलीं तो ठीक, नहीं तो राशि वापस की जाएगी। इस तरह जिन लाखों यात्रियों ने 15 से 18 दिन पहले टिकट बुक कराए हैं, उनकी राशि पर रेलवे को इतने दिन तक ब्याज भी मिलेगा। यह कमाई का जरिया है।

अब तो सुविधा शुल्क से छूट मिले : भोजपुरी एकता मंच के अध्यक्ष कुंवर प्रसाद ने कहा है कि दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में आम नागरिकों को गैर जरूरी शुल्क से छूट मिलनी चाहिए थी। ऐसा करने के बजाय महामारी में भी रेलवे सुविधा शुल्क ले रहा है, यह गलत बात है। सरकार को चाहिए कि वह इस पर एक बार विचार करे और सुविधा शुल्क खत्म करने के बारे में सोचे। यह वक्त जनता पर बोझ डालने का नहीं है।

ऐसे लगते हैं 15 व 30 रुपये

15 रुपये : ट्रेन में स्लीपर श्रेणी का टिकट खरीदने पर यह सुविधा शुल्क लगता है। यह शुल्क मूल किराये से अलग होता है।

30 रुपये : ट्रेन में एसी श्रेणी का ऑनलाइन टिकट खरीदने पर यह सुविधा शुल्क चुकाना पड़ता है।

जब ट्रेनें चलनी तय नहीं हैं तो रेलवे ऑनलाइन टिकट क्यों बेच रहा है। यह तो गलत है, टिकट ही नहीं बेचना चाहिए था। ऐसे में लोग घर बैठे-बैठे नुकसान में जा रहे हैं। यदि बुकिंग बंद रहती तो लोगों को उम्मीद ही नहीं रहती और वे बुकिंग नहीं कराते। ऐसा करने से उन्हें नुकसान नहीं होता।

– निरंजन वाधवानी, पूर्व सदस्य मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति, भोपाल

सुविधा शुल्क पूर्व से तय है। यदि ट्रेनें कैंसिल होती हैं तो पूरा किराया वापस दिया जाता है, लेकिन यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

–सिद्धार्थ सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता आइआरसीटीसी

ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति

- रेवांचल एक्सप्रेस – हबीबगंज-रीवा के बीच चलने वाली इस ट्रेन में स्लीपर श्रेणी में 83 वेटिंग।
- भोपाल एक्सप्रेस- हबीबगंज से हजरत निजामुद्दीन के बीच इस ट्रेन के स्लीपर श्रेणी में कन्फर्म टिकट नहीं, आरएसी है।
- पातालकोट एक्सप्रेस – भोपाल से नई दिल्ली के बीच सभी श्रेणियों में 29 वेटिंग।
- मालवा एक्सप्रेस – भोपाल से दिल्ली के बीच स्लीपर में 80 वेटिंग, बाकी श्रेणी में भी वेटिंग।
- मंगला एक्सप्रेस – भोपाल से मुंबई के बीच स्लीपर में 80 वेटिंग, अन्य श्रेणियों में भी वेटिंग है।
- हजरत निजामुद्दीन-एलटीटी एक्सप्रेस – सभी श्रेणियों में भोपाल से मुंबई के बीच वेटिंग है।

(नोट – यह वेटिंग 15 अप्रैल तक की है, जो 10 अप्रैल की स्थिति में थी।)

कह के रहेंगे माधव जोशी

4
दैनिक जागरण
रविवार 12 अप्रैल 2020
www.jagran.com

तेलंगाना, बंगाल और महाराष्ट्र में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा

उठाया कदम ▶ महाराष्ट्र के सीएम ने कहा– कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ममता का दावा– पीएम ने पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाने की कही है बात

चंद्रशेखर राव बोले, सख्ती से लागू करेंगे नियम

जेएनएन, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए महाराष्ट्र, बंगाल और तेलंगाना ने भी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। सबसे पहले ओडिशा ने इस महीने तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया था, जिसके बाद पंजाब ने भी एक मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की थी। कोरोना से पैदा हुए हालात की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव ने अपने-अपने राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से अभी देशभर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

वेबकास्ट के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लॉकडाउन के दौरान स्थानीय हालात को देखते हुए नरमी और सख्ती बरती जा सकती है। उद्धव ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या सर्वाधिक इसलिए है क्योंकि मुंबई एवं पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा होने के चलते शुरू से ही यहां विदेश से संक्रमित आते गए। इसके अलावा राज्य में बड़े पैमाने पर जांच भी की जा रही है। महाराष्ट्र में पूरे देश की तुलना में सर्वाधिक 33,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। इसमें 19,540 जांच मुंबई में की गई है।

राज्य में गंभीर मरीज कम : मुख्यमंत्री ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना रोगियों की संख्या अवश्य पूरे देश की तुलना में ज्यादा है। लेकिन इनमें गंभीर लक्षणों वाले रोगी पांच फीसद ही हैं और वह भी कुछ क्षेत्रों में ही सीमित हैं।

मरने वालों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित ज्यादा : मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक इस महामारी के चलते जान गंवाने वाले लोगों में पहले से अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या ही अधिक है। उद्धव ने संकेत दिया कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की सीमा बढ़ने के बावजूद कृषि एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को उनके कार्य में छूट देने की व्यवस्था रखी जाएगी।

देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न और सब्जियों आदि की आपूर्ति सुचारु रखने के लिए बड़ी संख्या में ट्रक ढुलाई में लगे हुए हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के नवी मुंबई में थोक सब्जी मंडी के बाहर कतार में खड़े वाहन। प्रेट

ड्रोन से होगी निगरानी

ममता ने कहा कि कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी और वहां लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जाएगा। हालांकि, इस दौरान राशन व दवा समेत आवश्यक सामान की दुकानें खुली रहेंगी।

बंगाल में स्कूल-कॉलेज में 10 जून तक छुट्टी : ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए अगले दो सप्ताह काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। ममता ने कहा कि बंगाल सरकार भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है और हम केंद्र के फैसले के साथ हैं। ममता ने इसी के साथ बंगाल में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रखने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 10 जून तक बंद रखने का भी ऐलान किया। ममता ने कहा कि हम सभी को और अधिक सतर्कता बरतते हुए घरों में रहना चाहिए।

कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन एक मात्र उपाय : हैदराबाद में चंद्रशेखर राव ने पत्रकारों को प्रदेश में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार बहुत सख्ती के साथ इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए ही कोरोना के प्रसार को रोका जा सकता है। चंद्रशेखर राव ने पहले ही लॉकडाउन को बढ़ाने का समर्थन किया था।

पंजाब में लंगर पर रोक की तैयारी

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने कहा, लंगर न बांटें लोग
- जालंधर के डीसी प्रशासन को राशन पहुंचाने की कर चुके हैं अपील

पंजाब में मोहाली का जवाहरपुर गांव कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। तीन हजार की आबादी वाले इस गांव में 34 केस पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि कई की रिपोर्ट आनी बाकी है। सरपंच और पंच भी पॉजिटिव हैं। माना जा रहा है कि इस गांव में कोरोना वायरस के बड़े पैमाने पर संक्रमण का कारण लंगर बांटना रहा। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी लंगर बांटे जा रहे हैं, जहां टूट रहे एहतियात बहुत भारी पड़ सकते हैं। लिहाजा लंगर पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है।

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने लंगर बांटने से लोगों को मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस एप तैयार कर रही है जिस पर सामाजिक संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद लोग राशन प्रशासन को पहुंचा सकते हैं, जिसे बांटने का काम पुलिस ही करेगी। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा पहले ही लोगों से अपील कर चुके हैं कि वे प्रशासन को राशन दें, खुद न बांटें। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी लोगों को लंगर बांटने से मना कर रखा है। दरअसल रोपड़ में कोरोना वायरस से जिस सरपंच की मौत हुई वह भी लंगर बांटते थे। जालंधर में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव आने वाले कांग्रेस नेता भी लोगों के बीच राशन बांटते थे। ऐसे में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

घरों में वितरित किया जाए सूखा राशन

मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इस तरह की शिकायतें आने लगी हैं जिनमें विधायकों ने कहा है कि लंगर की जगह लोगों के घरों में सूखा राशन मुहैया करवाया जाए। इसे आम लोगों व संस्थाओं की बजाय प्रशासन वितरित करे। सरकार की हिदायतों का पूरा पालन हो। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इस पर गौर किया जा रहा है।

अव्यवस्था पर दिखाएं सख्ती

प्रथम पृष्ठ से आगे

पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। वहीं डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों और पूर्वोत्तर एवं कश्मीर के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की निंदा करते हुए ऐसी हरकतों से सख्ती से निपटने की सलाह दी। पीएम ने कृषि कार्यों और कारोबार को लॉकडाउन से राहत दिए जाने की बात कही, साथ ही यह सुझाव भी दिया कि मंडियों में भीड़ को रोकने के लिए कृषि उपज के प्रत्यक्ष मार्केटिंग को प्रोत्साहित किया जाए।

आर्थिक महाशक्ति बनने का मौका : आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने और देश को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलने करने का अवसर है। इसके लिए सभी को एकजुट प्रयास करना होगा। बैठक में अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने कोरोना से लड़ने के लिए विशेष आर्थिक संसाधन, चिकित्सा उपकरणों के साथ केंद्रीय फंड के अपने लंबित वित्तीय फंड तत्काल दिए जाने की मांग की।

इस बैठक में भी आठ अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक जैसी ही सियासी एकजुटता दिखी। ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, उद्धव ठाकरे से लेकर अरविंद केजरीवाल सरीखे विपक्ष शासित राज्यों के सीएम हों या योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार और शिवराज सिंह जैसे भाजपा-एनडीए शासित राज्यों के सीएम कोरोना से लड़ाई में सभी के सुर करीब-करीब एक जैसे ही थे।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

लॉकडाउन में मजदूरों की पिटाई के दावे निकले गलत

Vishvas News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस मजदूरों को बेरहमी से पीट रही है। वायरल हो रही पोस्ट में पिटाई से चोटिल लोगों की तस्वीरें भी हैं। हालांकि पड़ताल में यह दावा गलत साबित हुआ।

पड़ताल : वायरल पोस्ट में दो तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। सच्चाई जानने के लिए दोनों तस्वीरों को गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया गया। इसमें 23 मार्च 2018 को किए गए ट्वीट के मुताबिक पहली तस्वीर बांग्लादेश के ढाका की है। ट्विटर यूजर 'नील आकाश' ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, 'बांग्लादेश के ढाका के शांतिगनर इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने एक रिक्शा चलाने वाले मजदूर को बुरी तरह पीटा।' इन तस्वीरों की लोकेशन को लेकर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह साफ है कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर 2018 से हैं जबकि लॉकडाउन की घोषणा 24 मार्च 2020 को की गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर को लेकर जब गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया गया तो एक फेसबुक यूजर की पोस्ट में मिली जो 17 जुलाई 2019 से सोशल मीडिया पर है। इसके अलावा सोशल मीडिया सर्च में पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से जारी किया गया एक ट्वीट मिला, जिसमें इन दोनों तस्वीरों को लेकर खंडन और चेतावनी जारी की जा चुकी है। दरअसल, सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल से जोड़कर वायरल किया गया था। इसके बाद पुलिस की तरफ से 27 मार्च 2020 को जारी किए खंडन में कहा गया है, 'कहीं और की तस्वीरों को पश्चिम बंगाल से जोड़कर वायरल किया जा रहा है, ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'

निष्कर्ष : लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के दावे के साथ वायरल हो रहा पोस्ट फर्जी है। जिन तस्वीरों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है, वे भारत में लॉकडाउन की घोषणा से काफी समय पहले की हैं।

क्या है वायरल पोस्ट में

फेसबुक यूजर 'दीपक कुमार मालो' ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'जितना आज दिहाड़ी, रेहड़ी, हाइवे पर चलते लोगों को मारकर सख्ती की जा रही है। अगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कर ली जाती तो भारत सुरक्षित रहता।'

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें: 9205 270 923

दिल्ली से पैदल लौट रहा कटिहार का युवक भदोही में संक्रमित

जासं, कटिहार : लॉकडाउन के कारण दिल्ली से पैदल लौट रहे मजदूरों के जत्थे में शामिल कटिहार का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसे भदोही में क्वारंटाइन किया गया था। संक्रमित युवक को मिर्जापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

युवक के साथ चल रहे अन्य मजदूरों के सैंपल भी भदोही प्रशासन ने जांच के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) भेजे गए हैं। संक्रमित मजदूर के जत्थे में शामिल अन्य मजदूर कटिहार के नहीं हैं। 18 वर्षीय युवक दिल्ली में एक गैराज में काम करता था। वह करीब सौ से अधिक मजदूरों के साथ बिहार लौट रहा था। भदोही में मजदूरों को रोककर क्वारंटाइन किया गया था।

जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि युवक के पॉजिटिव होने की सूचना मिली है। वहीं, उसके साथ के मजदूरों को भी वहीं क्वारंटाइन कर लिया गया है। सूचना के आधार पर संदिग्धों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग अभी जहां हैं वे वहीं रहें। अन्यथा कोरोना संक्रमण फैलता रहेगा और इसकी चपेट में आकर लोगों की मौत भी हो सकती है।

तब्लीगियों की जानकारी छिपाने पर दो प्रधानों के अधिकार सीज, लगेगा रासुका

बदायूं स्थित भवानीपुर खल्ली गांव में निरीक्षण के दौरान पुलिस-प्रशासन के अधिकारी। जागरण

जागरण संवाददाता, बदायूं

- भवानीपुर खल्ली की प्रधान नसरीन व पूर्व प्रधान रईस अहमद तथा भवानीपुर खैरू की प्रधान गुलनाज के घर सहित अन्य गांवों में संक्रमित व्यक्ति के ठहरने की जानकारी प्रधानों ने छिपाई थी। इसलिए, इनके अधिकार सीज कर दिए गए हैं। इन्हें बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ करने को कहा गया है। इनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल प्रधानपति और पूर्व प्रधान को हिरासत में ले लिया गया है। मुतवल्ली पर भी एनएसए की कार्रवाई होगी।
- कुमार प्रशांत, जिलाधिकारी।

तब्लीगियों की जानकारी छिपाना उप्र के बदायूं स्थित सहसवान क्षेत्र के दो ग्राम प्रधानों को भारी पड़ा गया। डीएम ने भवानीपुर खल्ली की प्रधान नसरीन और भवानीपुर खैरू की प्रधान गुलनाज बेगम के अधिकार सीज करते हुए उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) भी लगाया जाएगा। अधिकार सीज होना और बर्खास्तगी की प्रक्रिया बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फिलहाल खल्ली की प्रधान नसरीन के पति सरफराज और पूर्व प्रधान रईस अहमद को हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। पूर्व प्रधान रईस अहमद मस्जिद के मुतवल्ली भी हैं। बता दें कि सहसवान क्षेत्र में अब तक दो कोरोना पॉजिटिव तब्लीगी मिल चुके हैं।

शुक्रवार देर रात भवानीपुर खल्ली की मस्जिद में मिले आंध्र प्रदेश के चित्तूर के 10 तब्लीगियों में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी व अन्य अधिकारी शनिवार को गांव में पहुंचे। यहां पड़ताल में पता चला कि एक मार्च को तब्लीगी जमात से जुड़ी पांच महिलाएं और पांच पुरुष यहां पहुंचे थे। दो दिन रुकने के बाद वे सहसवान की तहसील वाली मस्जिद में गए जहां से 14 मार्च को फिर से वापस भवानीपुर पहुंच गए। लेकिन जब प्रशासन ने तब्लीगियों के बारे में रिपोर्ट मांगी तो प्रधान व उनके पति और पूर्व प्रधान ने जानकारी छिपा ली।

एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी के अनुसार, भवानीपुर खल्ली की प्रधान नसरीन के पति सरफराज और पूर्व प्रधान रईस अहमद को हिरासत में लिया गया है। जांच के बाद ग्राम प्रधानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बंगाल में पांच लोगों की सामूहिक रूप से पिटाई, एक की मौत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- तृणमूल नेता व उपप्रधान समेत 20 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज
- हत्या के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपित फरार

बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के संदल बिल इलाके में लॉकडाउन के दौरान भी भीड़ ने पांच लोगों की सामूहिक रूप से पिटाई कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान असरफ गाजी के रूप में हुई है। इस मामले में इलाके के तृणमूल कांग्रेस के नेता व पंचायत के उपप्रधान जयनाल आवेदिन गाजी को मुख्य आरोपित बताया जा रहा है। वहीं, जयनाल का आरोप है कि असरफ उसकी हत्या के लिए आया था। इस दौरान लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई।

असरफ के परिवार का दावा है कि जयनाल के करीबी शुक्रवार दोपहर असरफ समेत पांच लोगों को बुलाकर साथ ले गए थे। इसके बाद उन लोगों को एक पेड़ से बांध कर लाठी से जमकर पीटा गया, जिससे असरफ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य लोगों को गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असरफ की मां ने घटना में तृणमूल नेता व उपप्रधान समेत 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपित फरार है। यहां सवाल यह उठ रहा है कि लॉकडाउन में इतने लोग एक जगह कैसे जमा हुए? पुलिस क्या कर रही थी।?

पुरानी दुश्मनी का नतीजा बताया जा रहा : सूत्र बताते हैं कि यह घटना पुरानी दुश्मनी की वजह से हुई है। आरोप है कि 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान जयनाल पर गोली चली थी, लेकिन गोली जयनाल को नहीं बल्कि उसकी मां को लग गई थी। इसके बाद उसने असरफ और उसके दो साथी करीमुल्लाह, नूर इस्लाम के खिलाफ थाने में हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कुछ समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर मुक्त होकर असरफ तमिलनाडु में काम करने के लिए चला गया था। कुछ दिन पहले ही वह तमिलनाडु से गांव लौटा था। जयनाल का आरोप है कि अशरफ अपने साथियों के साथ हथियार लेकर मेरी हत्या करने के लिए आया था।

तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में संघर्ष : कोलकाता से सटे दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती में लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच जमकर झड़प और गोलीबारी हुई। इसमें तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया गया है कि शुक्रवार को बासंती थाने क्षेत्र के मोलखली गांव के निकट सड़क पर 40-50 तृणमूल कार्यकर्ता एकत्रित थे। किन्हीं बातों को लेकर अचानक विवाद हुआ और वहां एक दूसरे मारपीट करने लगे। इसके बाद दो गुटों में जमकर हिंसा शुरू हो गई और गोलीबारी होने लगी। तृणमूल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। इस झड़प में जख्मी तृणमूल के तीन कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान यह दूसरी बार है, जब बांसती में तृणमूल व युवा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है।

मेरठ में कार्रवाई करने गई पुलिस पर पथराव, सिटी मजिस्ट्रेट-दारोगा घायल

जागरण संवाददाता, मेरठ

अराजकता

- हाटस्पॉट को सील करने गई थी पुलिस-प्रशासन की टीम
- मस्जिद के पास पहले जमा भीड़ ने किया पथराव, मुतवल्ली सहित आठ पकड़े

पुलिस-प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अराजक तत्व इस जंग में बाधा डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मेरठ के जली कोठी क्षेत्र को सील करने गई पुलिस-प्रशासन की टीम पर दरी मस्जिद के पास भीड़ ने पथराव कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट और एक दारोगा घायल हो गए। टीम ने भागकर जान बचाई। इसके बाद आरएएफ बुलाकर इलाके को सील किया गया। पुलिस ने मुतवल्ली सहित आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आठ नामजद सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

तीन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जली कोठी क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया। शनिवार दोपहर सिटी मजिस्ट्रेट सतेंद्र सिंह और थाना प्रभारी रविंद्र कुमार पुलिस बल के साथ हॉट स्पॉट को सील करने गए थे। दरी मस्जिद के पास पहले से ही भीड़ जमा थी। पुलिस ने सील के लिए निशानदेही शुरू की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट सतेंद्र सिंह और दारोगा मुकेश घायल हो गए। सूचना मिलने पर एसपी सिटी पुलिस और आरएएफ को लेकर मौके पर पहुंचे। पथराव करने वाले आरोपितों के खिलाफ देहलीगेट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जली कोठी क्षेत्र को सील करने पुलिस टीम, जिस पर भीड़ ने पथराव किया। जागरण

एसएसपी अजय साहनी बोले, आरोपितों पर लगेगा रासुका

एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने, धारा 144 का उल्लंघन करने तथा 3 महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। सभी पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। वीडियो के आधार पर अन्य आरोपितों को चिह्नित किया जा रहा है। घरों से बाहर निकलने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। ड्रोन से उक्त क्षेत्र की लगातार निगरानी की जाएगी।

कथित प्रगतिशील वर्ग में तब्लीगी जमात को लेकर निंदा का सुर धीमा दिखा है

प्रथम पृष्ठ से आगे

मनीष तिवारी का कहना है कि अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर आप दूसरे पक्ष के कट्टरपंथियों को मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कथित प्रगतिशील वर्ग में तब्लीगी जमात को लेकर निंदा का सुर धीमा दिखा है। इनके खिलाफ पाकिस्तान और इस्लामी देशों में ज्यादा सख्त रुख दिखाई दिया है।

कांग्रेस नेता ने मुख्यधारा के मुसलमानों से भी कहा कि अगर वे ऐसी घटनाओं की निंदा नहीं करेंगे तो लोगों को सभी मुसलमानों की तुलना जमात से करने का मौका मिल जाएगा। अपनी इस साफगोई को लेकर मनीष तिवारी को सोशल मीडिया पर अपनी ही पार्टी के नेता शकील अहमद से लेकर दिल्ली कांग्रेस की नेता यास्मीन किदवई के भी सवालों का सामना करना पड़ा। एक तथाकथित मुस्लिम बुद्धिजीवी ने तो तंज कसते हुए यहां तक पूछ डाला कि वे भाजपा में कब शामिल हो रहे हैं। मनीष तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी मंत्री से इस तरह के सवाल क्यों नहीं किए जाते?

पीड़ित होने का कार्ड न खेलें : सोशल मीडिया पर छेड़ी गई इस बहस के बारे में दैनिक जागरण के पूछे जाने पर मनीष तिवारी ने कहा 'राम जन्मभूमि के दिनों से ही मेरा स्पष्ट मानना रहा है कि जब तक आप अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें बराबर का नजरिया अपनाना ही होगा। तब्लीगी जमात को विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि कोरोना जेहाद का। इसमें तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादियों का पीड़ित होने (विक्टिम) का कार्ड उनके स्वयं के लिए भी विध्वंसकारी है।'

पार्टी में मिला समर्थन : मनीष तिवारी के समर्थन में भी लोग आगे आए। उनकी ही पार्टी के नेता और लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले प्रमोद कृष्णम ने कहा कि तब्लीगी जमात की निंदा करने के बजाय तथाकथित सेक्युलरिस्ट लिबरल पीड़ित कार्ड खेल रहे हैं।

उन्होंने कथित प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन्होंने आरएसएस, विहिप और बजरंग दल की आलोचना कर अपनी राजनीति को संवारा है वे क्यों मौन हैं और अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हैं?

पीएम और सीएम पर अभद्र टिप्पणी पर उप्र कांग्रेस के प्रदेश सचिव गिरफ्तार

जासं, अमरोहा : उप्र कांग्रेस के प्रदेश सचिव को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लॉकडाउन उल्लंघन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी के आरोप हैं। कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं लोकसभा क्षेत्र अमरोहा से कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके सचिन चौधरी ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस की थी। कहा था कि कोरोना से किसी को नुकसान हो या न हो लेकिन, भुखमरी के हालात बन रहे हैं। गरीब लोग जरूर मर जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सरकार की ओर से चलाई जा रही रसोई को दिखावा करार दिया। शनिवार को नगर कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने व पीएम व सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

जमाती की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपये का इनाम

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर

मास्क न लगाने पर 300 रुपये जुर्माने की मुनादी

कौशांबी : कोरोना से जंग में पंचायतीराज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का वितरण कराया। डीपीआरओ की पहल पर ग्राम पंचायतों ने निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति बगैर मास्क लगाए घर से बाहर निकलेगा, उससे 300 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध मुनादी भी कराई जा रही है। दरअसल, जिला प्रशासन ने मास्क लगाए या अंगोछा लपेटे बिना घर से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। डीपीआरओ गोपाल ओझा ने कहा है कि जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। बताया कि शनिवार को एक हजार मास्क वितरित किए गए।

कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए पुलिस-प्रशासन ने दिन रात एक कर रखा है, लेकिन दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज से लौटे जमाती सरकार की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। उप्र के बुलंदशहर जिले में सैकड़ों जमाती छिपे हैं। अब इनकी तलाश के लिए बुलंदशहर पुलिस ने नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत छिपे जमातियों की सूचना देने वाले को दस हजार रुपये का नकद इनाम देने का एलान किया गया है।

बुलंदशहर पुलिस को इनपुट मिला है कि बुलंदशहर जिले से दिल्ली गए आधे से ज्यादा जमाती अभी गायब हैं। इनका पता नहीं चलने से पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की नींद उड़ी हुई है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि लापता जमातियों की सूचना देने वाले को दस हजार का नकद इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। सूचना एसपी सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव दो मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। एसएसपी ने जिले में छिपे जमातियों व उन्हें पनाह देने वालों से अपील की है कि कहीं भी जमाती ठहरे हैं तो वह खुद प्रशासन के पास आ जाएं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। केवल उनका चेकअप होगा। यदि पुलिस जबरन लेकर आई तो फिर मुकदमे दर्ज होंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एससपी ने बताया कि मुखबिर तंत्र के निजी फंड से इनाम दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,761 और देश में आठ हजार के पार संक्रमित

वायरस का प्रकोप ▶ एक दिन में और 31 लोगों की गई जान, मुंबई में सबसे ज्यादा 12 मौतें, आंध्र प्रदेश में 24 नए केस में से 17 जमाती

नई दिल्ली, एजेंसियां : देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आती नजर नहीं आ रही। शनिवार को भी इस महामारी ने 31 लोगों की जान ले ली और मरने वालों का आंकड़ा तीन सौ के करीब पहुंच गया है। साढ़े सात सौ के करीब नए मामले भी सामने आए और संक्रमितों की संख्या आठ हजार से ज्यादा हो गई है। हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक इस महामारी से 7,529 लोग संक्रमित हुए हैं, 242 लोगों की मौत हुई है और 643 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं।

राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों में अंतर को लेकर अधिकारियों का कहना है कि राज्यों की संबंधित इकाइयों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़े मिलने में देरी के कारण यह अंतर रहता है। कई निजी एजेंसियां सीधे राज्यों से आंकड़े जुटाती हैं। राज्यों से मिली सूचनाओं के मुताबिक शनिवार को देशभर में 739 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 8,279 पर पहुंच गया। विभिन्न राज्यों में अब तक उपचार के बाद 807 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। शनिवार को 31 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अकेले माहाराष्ट्र में ही 17 मौतें हुई हैं। अकेले मुंबई में 12 और पुणे में तीन लोगों की जान गई है। इनमें एक मौत धारावी में भी हुई है। धारावी में मरने वालों की संख्या चार हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में पांच, मध्य प्रदेश और गुजरात में तीन-तीन और राजस्थान, केरल और तमिलनाडु में एक-एक व्यक्ति की जान गई है। देशभर में मृतकों की संख्या 279 हो गई है।

अगर हम राज्य के हिसाब से कोरोना के प्रभाव की बात करें तो महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। शनिवार को यहां 187 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 1,761 हो गई है। अकेले मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 12 सौ से करीब पहुंच गया है।

राजस्थान में 139 नए केस मिले : राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा ने भले ही सख्त पाबंदियों के चलते कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो इस महामारी पर नियंत्रण नहीं दिख रहा है। राज्य में शनिवार को 139 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 700 पर पहुंच गया।

दक्षिण भारत को राहत नहीं : अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो किसी भी प्रदेश से इस महामारी से राहत की खबर नहीं मिल रही है। तब्लीगी जमातियों के कारण इन राज्यों में हालात अभी खराब ही होती जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में शनिवार को 24 नए मामले सामने आए, जिनमें से 17 तब्लीगी जमात से जुड़े हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा चार को पार करते हुए 405 पर पहुंच गया है। केरल में पिछले कुछ समय से कम मामले मिल रहे हैं। 10 नए केस के साथ वहां अभी तक 373 केस सामने आए हैं।

तमिलनाडु में नए मामलों में कुछ कमी तो आई है, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में अभी भी यहां रोजना ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को 58 नए केस मिले और संक्रमितों का आंकड़ा 969 पर पहुंच गया। कर्नाटक में आठ नए मामले मिले हैं और इनकी संख्या 215 हो गई है।

गुजरात-कश्मीर में भी हाल बेहाल : गुजरात में भी हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे। रोजाना नए मामलों में कमी नहीं आ रही है। 90 नए केस के साथ अभी तक राज्य में कुल सामने आए संक्रमितों की संख्या 468 हो गई है। जम्मू-कश्मीर में 17 नए केस मिले हैं और कुल संक्रमित 224 हो गए हैं। जबकि, 13 नए मामलों के साथ उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 456 पर पहुंच गई है। इनमें आठ जमाती हैं। हिमाचल में दो नए मामले सामने आए हैं। यहां कुल 32 संक्रमित हो गए हैं। पंजाब में नौ नए मामले सामने आए हैं और संक्रमित 160 हो गए हैं।

दिल्ली में 166 नए केस : राजधानी दिल्ली में शनिवार को भी 166 नए केस सामने आए। इनमें भी ज्यादातर जमाती ही हैं। कुल संक्रमितों की संख्या एक हजार को पार कर 1069 हो गई है। मध्य प्रदेश में 12 नए केस मिले हैं और संक्रमित 595 हो गए हैं।

महाराष्ट्र के कराड में शनिवार को कोरोना वायरस का शिकार बने व्यक्ति का अंतिम संस्कार स्वास्थ्यकर्मियों की मौजूदगी में आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए किया गया। इस दौरान सभी प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए थे। प्रेट्र

तेलंगाना में 85 फीसद संक्रमित जमाती

तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री इटाला राजेंद्र ने कहा है कि उनके राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों में 85 फीसद तब्लीगी जमात से जुड़े लोग हैं। इनका इलाज हो जाता है तो राज्य में पॉजिटिव केस में भारी कमी आएगी और उसके बाद वायरस के प्रसार को रोकना भी आसान होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक साढ़ आठ हजार लोगों की कोरोना जांच की गई है।

एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामलों वाले पांच राज्य

राज्य	नए मामले	कुल मामले
महाराष्ट्र	187	1,761
दिल्ली	166	1,069
राजस्थान	139	700
गुजरात	90	468
तमिलनाडु	58	969

मरीजों के लिए 586 अस्पतालों में 11,500 आइसीयू बेड : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में कोविड-19 अस्पतालों के तौर पर 586 डेडिकेटेड अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जिनमें एक लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड और 11,500 आइसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर इनकी संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में शारीरिक दूरी, लॉकडाउन और कंटेनमेंट के अन्य प्रयास बेहद अहम हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पूर्व तैयारी, पूर्व सक्रिय और कुछ हद तक सीमा से अधिक तैयारी की रही है। आयुष मंत्रालय ने श्वसन संबंधी स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के संबंध में गाइडलाइंस तैयार की हैं। जिलों से इसे जिलास्तरीय आपात योजना में भी शामिल करने के लिए कहा गया है।

देश में कुल संक्रमित

राज्य	संक्रमित
महाराष्ट्र	1,761
दिल्ली	1,069
तमिलनाडु	969
राजस्थान	700
मध्य प्रदेश	595
तेलंगाना	487
उत्तर प्रदेश	456
आंध्र प्रदेश	405
केरल	373
गुजरात	468
कर्नाटक	215
जम्मू-कश्मीर	224
हरियाणा	166
पंजाब	160
बंगाल	122
बिहार	61
ओडिशा	44
उत्तराखंड	35
हिमाचल प्रदेश	32
असम	28
चंडीगढ़	18
छत्तीसगढ़	18
लद्दाख	15
झारखंड	17
अंडमान-निकोबार	11
गोवा	7
पुडुचेरी	7
मणिपुर	2
मिजोरम	1
त्रिपुरा	2

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन में कच्चे माल की कमी

सुनील शर्मा, सोलन

कोरोना वायरस के उपचार में कारगर बताई जा रही मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग देश-विदेशों में बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार भी एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब बद्दी-बरोटीबाला-नालागढ़ (बीबीएन) की तरफ ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि इस दवा का उत्पादन बढ़ाया जाए और कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मियों को वापस लाने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल के बीबीएन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तैयार करने वाले उद्योग तो 50 हैं, लेकिन कर्फ्यू और कच्चा माल न होने पर 10 कंपनियां ही दवा का उत्पादन कर पा रही हैं। अगर पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होता है तो दवा उत्पादन रफ्तार पकड़ सकता है।

बीबीएन में 400 फार्मा उद्योग : देश-विदेश में इस दवा की अचानक मांग बढ़ने पर केंद्र सरकार ने बीबीएन में स्थापित जिड्स कैडिला, सिपला, टोरेंट फार्मा, डॉ. रेड्डी लैब आदि उद्योगों में उत्पादन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन सोलन ने फार्मा कंपनियों को दूसरे राज्यों व प्रदेश के अन्य जिलों में फंसे कर्मचारियों को लाने की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की है। हिमाचल में 500 के करीब फार्मा उद्योग हैं। इनमें ले 400 उद्योग बीबीएन में हैं।

बीबीएन देश ही नहीं बल्कि विदेशों की मांग पूरा करने में सक्षम है। वर्तमान में 10 उद्योगों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन हो रहा है। हालांकि 50 उद्योगों के पास यह दवा बनाने का लाइसेंस है।

– नवनीत मरवाह, राज्य दवा नियंत्रक

लाइसेंस हमारे पास है, लेकिन कच्चा माल न मिलने के कारण उत्पादन नहीं कर रहे हैं। अगर कच्चा माल उपलब्ध होता है तो कंपनी प्रतिदिन ढाई लाख गोलियों का उत्पादन करेगी।

– विनोद गुप्ता, मैरिडियन फार्मा समूह

दवा उत्पादन के लिए कच्चा माल मुंबई से आता है। **सभी राज्यों में कर्फ्यू लगने से कच्चा माल लाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर तैयार नहीं है।**

– राजेश गुप्ता, अध्यक्ष, हिमाचल इंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन

निजी लैब में मुफ्त कोरोना टेस्ट के आदेश में बदलाव की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल हुई है, जिसमें सभी सरकारी और निजी लैब में कोरोना की जांच मुफ्त किए जाने के आदेश में संशोधन करने की मांग की गई है। दिल्ली के रहने वाले हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में यह हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है, जिसमें कोर्ट से गत आठ अप्रैल के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया है। अर्जीकर्ता के वकील ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ऑनलाइन अर्जी देकर मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि अभी अर्जी पर सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने गत आठ अप्रैल को आदेश दिया था कि चाहे सरकारी लैब हो या निजी लैब, सभी में कोरोना की जांच मुफ्त में होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार को तत्काल प्रभाव से इस बारे में आदेश जारी करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की जांच एनएबीएल की मान्यता प्राप्त लैब या कोई और एजेंसी जिसे डब्ल्यूएचओ अथवा आइसीएमआर ने मंजूरी दी हो, वहीं होगी।

अर्जी में मुफ्त जांच के आदेश में संशोधन का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि यह महामारी देश में धीरे-धीरे बढ़ रही है और आने वाले सप्ताह में इसमें काफी बढ़ोतरी हो सकती है। यही समय है जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जांच की जरूरत है, ताकि महामारी को बढ़ने से रोकने के सरकार का प्रयास सार्थक हो सके। डॉक्टर कौशल कांत का कहना है कि आइसीएमआर की सलाह के मुताबिक आने वाले समय में टेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इससे सरकारी और निजी लैब दोनों पर मरीजों का दबाव बढ़ेगा। अगर निजी लैब में जांच को मुफ्त किया जाएगा तो कहीं न कहीं वह इससे बचने की कोशिश कर सकती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच करने के उद्देश्य में बाधा आएगी। जांच मुफ्त करने से आर्थिक दबाव बढ़ेगा और जांच की रफ्तार भी धीमी होगी। अर्जी में आठ अप्रैल के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए कहा गया है कि कोर्ट आदेश दे कि निजी लैब आइसीएमआर की 17 मार्च की एडवाइजरी के हिसाब से (प्रारंभिक जांच और कन्फर्म जांच मिला कर 4500 रुपये) जांच का शुल्क ले सकती हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मुफ्त जांच करेंगी, जिसकी सरकार तत्काल प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा कहा गया है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह म्युनिसिपल और पंचायत क्षेत्र में जांच लैब स्थापित करे ताकि सरकार द्वारा की जा रही मुफ्त जांच की क्षमता और संख्या बढ़ाई जा सके।

रेलवे ऑनलाइन साक्षात्कार कर भर्ती करेगा डॉक्टर

जासं, लखनऊ : कोरोना से निपटने के लिए अब उत्तर रेलवे ने लखनऊ रेल मंडल प्रशासन को बड़ी संख्या में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के आदेश दिए हैं। तीन महीने के लिए अस्थायी तौर पर संविदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की जाएगी। 134 पदों के लिए 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे से जूम व वाट्सएप वीडियो कॉलिंग से साक्षात्कार होगा। उत्तर रेलवे ने लखनऊ के चारबाग रेलवे मंडल अस्पताल को कोरोना के लिए तैयार किया है। अस्पताल में दो वेंटिलेटर लगा दिए गए हैं। अब कोरोना की जांच और उपचार के लिए अस्थायी तौर पर कांट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर (जीडीएमओ) के 12 और कांट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर (स्पेशलिस्ट) के 36 डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। जीडीएमओ का वेतन 75 हजार और स्पेशलिस्ट का वेतन 95 हजार होगा। वहीं, 86 स्टाफ नर्स की भी तैनाती होगी। इनका वेतन 54329 रुपये होगा। सभी जरूरी दस्तावेज के साथ 16 अप्रैल दोपहर तीन बजे तक srdponrlko@gmail.com पर एप्लीकेशन भेजना होगा।

इंडोनेशिया और थाइलैंड के 21 जमाती भेजे गए जेल

जागरण संवाददाता, बहराइच

- पासपोर्ट जब्त, गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
- दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के बाद उप्र के बहराइच में आकर छिपे थे

दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तब्लीगी जमात में शामिल होने के बाद उप्र के बहराइच जिले में आकर छिपे थाइलैंड व इंडोनेशिया के 21 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया। गत दिनों इन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। एहतियात के तौर पर सभी जमातियों को महिला अस्पताल के क्वारंटाइन शेल्टर में रखा गया था। शनिवार को जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर इन्हें जेल रवाना कर दिया गया।

निजामुद्दीन में आयोजित तब्लीगी जमात में इंडोनेशिया के 14 व थाइलैंड के सात जमाती शामिल हुए थे। वहां से ये लोग बहराइच आए थे। पुलिस के बार-बार अपील के बाद भी ये लोग बाहर नहीं आए। इसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर सभी जमातियों को शहर के मरकज व घरों से ढूंढ निकाला था।

इन पर पहचान छिपाने, जानबूझ कर संक्रमण फैलाने, महामारी अधिनियम सहित गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 28 मार्च से सभी जमाती क्वारंटाइन किए गए थे।

सीएमएस डॉ. डीके सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट निगेटिव आने की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने सभी जमातियों को सीधे जेल रवाना कर दिया। कोतवाल नगर आरपी यादव ने बताया कि पहचान छिपाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्हें जेल भेजा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी जमाती को अपने घरों में सह ने दें।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

विदेशी तब्लीगी जमातियों पर पुलिस ने महामारी, आपदा प्रबंधन, विदेशी विषयक अधिनियम व 188, 269 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

चिकित्सा कर्मियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करें राज्य : केंद्र

नई दिल्ली, एजेंसियां : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में वे अस्पताल या क्वारंटाइन केंद्र जा रहे डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट ने आठ अप्रैल को उक्त आदेश दिया था।

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने शनिवार को बताया कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

आकलन से साबित हुई लॉकडाउन की उपयोगिता

प्रथम पृष्ठ का शेष

लव अग्रवाल ने कहा कि गणितीय आकलन से लॉकडाउन और कंटेनमेंट के लिए उठाए गए कदमों की उपयोगिता साबित होती है। वैसे तो उन्होंने लॉकडाउन के जारी रहने के बारे में कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया। लेकिन यह साफ कर दिया कि कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए कड़े कंटेनमेंट उपाय जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट वाले इलाके को पूरी तरह सील किए बिना इस वायरस को रोकना संभव नहीं होगा।

भीलवाड़ा मॉडल का श्रेय राहुल गांधी को देने पर महिला सरपंच नाराज

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

- किस्मत गुर्जर बोली-यह समय राजनीतिक स्वार्थ-सिद्धि का नहीं
- सोनिया गांधी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व गहलोत सरकार को दिया था श्रेय

भीलवाड़ा जिले के देवरिया गांव की सरपंच किस्मत गुर्जर अपने गांव में सैनिटाइजेशन करती हुई। जागरण

कोरोना संक्रमण पर जीत के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की चर्चा चारों तरफ है। देश-विदेश में भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया जा रहा है। देश के कई राज्य के साथ ही विदेश से भी भीलवाड़ा में अपनाई गई रणनीति की जानकारी मांगी जा रही है। इस बीच भीलवाड़ा में कोरोना पर जीत का श्रेय शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को दिया तो राजनीतिक बवाल मच गया। राहुल और राज्य सरकार को श्रेय देने पर भीलवाड़ा जिले के देवरिया गांव की सरपंच किस्मत गुर्जर नाराज हो गईं। उन्होंने फेसबुक और ट्वीटर के जरिये अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा मॉडल के लिए सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को श्रेय दिया, जिससे मुझे दुखः हुआ है।

उन्होंने कहा है कि भीलवाड़ा मॉडल के पीछे यहां के आम लोगों, महिलाओं, स्वयंसेवी संगठनों एवं किसानों की कड़ी मेहनत है। राज्य सरकार जिस तरह से इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, उसी तरह अब राहुल गांधी ने भी इस तरह की कोशिश की है। लेकिन, यह स्थानीय लोगों की मेहनत का नतीजा है। यहां के लोगों ने कोरोना से लड़ने के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा। शारीरिक दूरी का पालन किया। इसके बाद कामयाबी मिली है। सरपंच ने कहा कि यह समय राजनीतिक स्वार्थ-सिद्धि का नहीं है। यह समय सतर्कता और संयम के साथ प्रतिदिन मेहनत करने का है । उल्लेखनीय है कि किस्मत गुर्जर गांव के विकास में काफी सक्रिय रहती हैं। भीलवाड़ा में जब कोरोना फैला तो सबसे पहले उन्होंने ही अपने गांव में खुद के खर्च से गांव में सैनिटाइजेशन कराया। वे महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर भी सक्रिय रहती हैं।

पीएम मोदी की अपील का असर : सरपंच किस्मत गुर्जर ने सोशल मीडिया पर लिखा हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से बहुत प्रभावित हुए हैं । यहां के लोग लॉकडाउन की पालना करने के साथ ही शारीरिक दूरी और साफ-सफाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं । डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ के साथ सहयोग करने को लेकर प्रधानमंत्री ने जो आग्रह किया है, उसका यहां के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है ।

बेवजह घूमने वालों को पुलिस सुनाएगी 'मस्कली 2.0' गाना

जागरण संवाददाता, जयपुर

लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को पुलिस मस्कली 2.0 गाना सुनाएगी। दरअसल, वह गाना के माध्यम से लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है। जयपुर पुलिस ने लोगों को घर में रहने के लिए अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट कर अनोखे ढंग से अपील की है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने हाल ही में रिलीज हुए मस्कली 2.0 गाने का इस पोस्ट में उदाहरण दिया है।

एक फोटो पोस्ट कर लिखा- अगर बाहर बेवजह घूमते दिखाई दिए तो एक कमरे में बंद कर बार-बार मस्कली 2.0 गाना सुनाया जाएगा। पुलिस ने पोस्ट में लिखा कि मत उड़ियो, तू डरियो। ना कर मनमानी, मनमानी। घर में ही रहियो। ना कर नादानी। ऐ मस्कली, मस्कली। जयपुर पुलिस ही नहीं, राजस्थान पुलिस के ट्वीटर हैंडल से भी कई बार लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे पोस्ट किए जाते रहे हैं। पुलिस ने फिल्म के डायलॉग और पोस्टर को ट्वीट करते हुए घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की सलाह दी थी। ट्वीट में लिखा गया था-घरेलू हिंसा है एक थप्पड़! मानसिक उत्पीड़न है एक थप्पड़! 1090, 112 डायल करें या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें।

उधर, जयपुर कलेक्टर जोगाराम, झुंझुनूं कलेक्टर यूडी खान और अजमेर कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों को फोन पर आग्रह कर रहे हैं कि वे लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहें। तीनों जिला कलेक्टर प्रतिदिन अचानक अपने-अपने जिले के किसी भी आम नागरिक को फोन कर पूछ रहे हैं कि उन्हें किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है।

कार्मिकों की मृत्यु पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कोरोना महामारी की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु होने पर सरकार उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए 50 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान करेगी। इस व्यवस्था का लाभ चिकित्सा विभाग की ओर से बीती सात अप्रैल को जारी किये गए शासनादेश से सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि के सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्थायी व अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को मिलेगा जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम, उपचार और बचाव कार्यों में लगे हैं। राजस्व विभाग ने इस बारे में शनिवार को शासनादेश जारी कर दिया है। मृत कार्मिक के आश्रितों को धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है।

कोरोना के चलते लड़की वालों ने कह दिया-टेस्ट के बाद ही करेंगे शादी

नईदुनिया, बिलासपुर

पंडितजी ने लड़का व लड़की की पत्रिका का वाचन कर लिया था। 25 गुण दोनों के मिल रहे थे। दोनों पक्ष ने सगाई की रस्म भी पूरी कर ली थी। अप्रैल में शादी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन खुलने तक आयोजन टाल दिया गया। इस बीच लड़की पक्ष ने शर्त रख दी। कहा कि लड़के का कोरोना टेस्ट कराएं। रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही शादी हो सकेगी। अब इस शर्त ने दोनों परिवार के बीच अनबन पैदा कर दी है। अब इसकी पूरे शहर में चर्चा हो रही है।

ये कहानी है बिलासपुर के तिवारी और शुक्ला परिवार की। मार्च के प्रथम सप्ताह में कोरोना को लेकर इतना भय नहीं था। सब-कुछ ठीक-ठाक था। तिवारी और शुक्ला परिवार के बीच रिश्ता तकरीबन तय हो गया था। तिवारी परिवार के सदस्य इस बात को लेकर खुश थे कि लड़की के लिए अच्छा वर मिल गया। लड़का एनटीपीसी पावर प्लांट में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत है। अच्छा खासा वेतन है। सबसे बड़ी बात ये कि बेटी पास में ही रहेगी। जांजगीर-चांपा का मूल निवासी तिवारी परिवार बिलासपुर में ही रहता है। जाहिर है बेटी भी नजरों के सामने रहेगी। यही सोचकर सगाई की रस्म भी पूरी कर दी। अप्रैल में विवाह की तारीख तय हो गई । सब कुछ अच्छा चल रहा था। बेटी पक्ष के लोग खरीदारी में भी व्यस्त हो गए थे। तब क्या पता था कि बेटी और दामाद की कुंडली में कोरोना किसी बुरे ग्रह की भांति सामने आ जाएगा। तय रिश्ते में खटास घोल देगा। लेकिन, हुआ ऐसा ही। देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना का खौफ कुछ ऐसा छाया है कि लोग अपनी तरफ से कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते। तिवारी परिवार के साथ भी यही हुआ। परिवार के सदस्यों ने लड़के वालों के सामने शर्त रख दी। लड़के को पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद आगे विवाह की तिथि मिल बैठकर तय करेंगे। यही बात लड़के वालों को खटक गई। दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव हो गया।

वेटी के भविष्य की चिंता सबसे जरूरी

तिवारी परिवार को इस बात की आशंका है कि एनटीपीसी पावर प्लांट में विदेश से भी तकनीकी अधिकारियों की टीम आती रहती है। इस कारण कोरोना को लेकर भय बना रहता है। लड़की के भविष्य का सवाल है तो कोरोना जांच करा लेने में बुराई ही क्या है।

लॉकडाउन के पालन की शर्त पर मिल रही जमानत

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ : देश इस समय कोविड 19 महामारी का प्रकोप को झेल रहा है। कार्यपालिका और विधायिका के साथ न्यायपालिका भी इस संकट में अपनी जिम्मेदारी पुरजोर तरीके से निभा रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट मुकदमों की सुनवाई के साथ लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कर रहा है।

हाई कोर्ट इन दिनों वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-कोर्ट का संचालन कर रहा है। अर्जेंट व जमानत के केस सुन रहा है। जमानत और दूसरे आदेश देते वक्त लॉकडाउन के मानदंडों के पालन करने का निर्देश दे रहा है।

इतना ही नहीं, लॉकडाउन की शर्तों का पालन करने का आश्वासन देने पर ही जमानत दी जा रही है। हाई कोर्ट के सभी 55 न्यायाधीशों ने पीएम राहत कोष में दस-दस हजार रुपये दिया है। व्यक्तिगत स्तर पर बड़ी संख्या में न्यायाधीशों ने पीपीई किट और अन्य राहत सामग्री की खरीद के लिए नकद राशि का भी योगदान दिया है।

बिग बॉस के घर में रहने से कहीं आसान है लॉकडाउन...

जागरण विशेष ▶ बिग बॉस प्रतिभागी पहलवान संग्राम सिंह ने सोशल मीडिया पर छेड़ा अभियान- हराओ कोरोना, चैंपियन बनो ना

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

लकवे को मात देकर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके पहलवान संग्राम सिंह अब कोरोना को हराने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़े हुए हैं। मशहूर टीवी शो बिग बॉस के प्रतिभागी रह चुके इस सेलेब्रिटी पहलवान के अभियान- हराओ कोरोना, चैंपियन बनो ना... को सराहा जा रहा है, जिसमें वह लोगों को घरों में बंद रहने के दौरान समय काटने और फिट रहने के टिप्स देते हैं। कहते हैं कि बिग बॉस के घर में बिताये गए साढ़े तीन महीने के समय की तुलना में यह समय काटना कहीं अधिक आसान है।

संग्राम कहते हैं कि लॉकडाउन के इस दौर में घर में कैद हो जाना लोगों के लिए अपनी तरह का पहला अनुभव है। खुद को और दूसरों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह आवश्यक भी है। लेकिन समय का बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य का खयाल भी जरूरी है ताकि समय आसानी से कट जाए। इसी बात को ध्यान में रख यह अभियान छेड़ा है। ताकि घरों में सिमटे लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनने के लिए प्रेरित कर सकूं।

वर्तमान में फिटनेस गुरु और प्रेरणादायी वक्ता की भूमिका निभा रहे संग्राम की इस अभिनव मुहिम से हर रोज हजारों लोग जुड़ रहे हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान, भारत गौरव अवार्ड समेत ढेरों पुरस्कारों से नवाजे जा चुके 34 साल के संग्राम ने दैनिक जागरण से कहा, मैं रोजाना दोपहर तीन से साढ़े तीन बजे तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट पर लाइव रहता हूं और शारीरिक-मानसिक मजबूती प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों और उपायों के बारे में बताता हूं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि घर में रहकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोग निराश न हों, उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। मैं लोगों को स्वस्थ रहने के नुस्खे बताता हूं। डिप्रेशन से बचने और इससे निकलने के रास्तों के बारे में समझाता हूं। खुद को प्रोत्साहित कैसे करें, लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग कैसे करें, अपने जीवन के लक्ष्यों को कैसे हासिल करें, यह सारी बातें अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताता हूं। जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा, यह अभियान जारी रहेगा।

मशहूर रियल्टी शो बिग बॉस के सातवें सीजन में प्रतिभागी रहे संग्राम ने कहा, 21 दिनों का लॉकडाउन बिग बॉस के घर में रहने से कहीं आसान है। मैंने बिग बॉस के घर में साढ़े तीन महीने बिताए हैं। वहां भिन्न स्वभाव के लोगों के साथ रहना पड़ता है, जिन्हें आप ठीक से जानते भी नहीं हैं, जबकि लॉकडाउन में सभी घर में अपने परिवार के साथ हैं। बिग बॉस के घर में न तो अपना परिवार होता है और ना ही स्वजनों से बातचीत ही हो पाती है। लॉकडाउन में लोगों के हाथ में मोबाइल है, मनोरंजन के ढेर सारे साधन मौजूद हैं, टीवी और अखबारों के जरिए देश-दुनिया की खबरें मिल रही हैं। बिग बॉस के घर में हम देश-दुनिया से बेखबर रहते थे। वहां एक-एक दिन बिताना बेहद मुश्किल था। संग्राम ने कहा, इस समय धैर्य बहुत जरूरी है। सरकार जो कह रही है, उसका हम सभी को कड़ाई से पालन करना चाहिए। बाहर जाकर अपने और अपने परिवार को खतरे में न डालें बल्कि घर में रहकर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और योग-प्राणायाम कर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। संग्राम ने कहा कि कोरोना संकट से उबरने के बाद उनकी फिर से रिंग में उतरने की योजना है। निगाहें अगले साल होने वाली विश्व चैंपियनशिप पर है।

पहलवान संग्राम सिंह लोगों को योग सिखाने के साथ व्यायाम के टिप्स भी दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर छेड़े गए अभियान के तहत प्रेरक बातें बताते संग्राम सिंह। सौजन्य : स्वत:

> सच मानिये, लॉकडाउन में अपने घर पर रहना बिग बॉस में बिताए गए उन दिनों से कहीं अधिक आसान और आरामदायक है। वहां एक-एक दिन काटना मुश्किल था, जबकि यह तो अवसर है जब स्वजनों का अधिक से अधिक साथ मिल रहा है।
> - संग्राम सिंह, अंतरराष्ट्रीय पहलवान

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

महज छह दिनों में ढाई साल के बच्चे ने दी कोरोना को मात

जागरण संवाददाता, लखनऊ

लखनऊ के केजीएमयू में अब तक भर्ती मरीजों में सबसे कम दिनों में हुआ ठीक

उप्र के सबसे कम उम्र के कोरोना पॉजिटिव मरीज ने बीमारी से जंग जीत ली है। उसने बगैर किसी दवा के खतरनाक वायरस को मात दी है। शनिवार को उसकी दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आई। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया।

लखनऊ के गोमती नगर निवासी महिला चिकित्सक कनाडा से लौटी थीं। उनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। केजीएमयू में इलाज के बाद वह घर पहुंचीं। इसके बाद उनके बच्चे, सास-ससुर को भी वायरस ने जद में ले लिया। छह अप्रैल को ढाई वर्षीय बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ (केजीएमयू) के संक्रामक रोग यूनिट में बच्चे को आइसोलेट किया गया। 48-48 घंटे पर दो टेस्ट कराए गए। दोनों रिपोर्ट निगेटिव आने पर शनिवार को बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉ. डी हिमांशु के मुताबिक, केजीएमयू में भर्ती मरीज 14 से 24 दिन में डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं, बच्चा छह अप्रैल को भर्ती हुआ। यह छह ही दिन में ठीक हो गया। उसे घर भेज दिया गया, मगर 14 दिन तक मां और बच्चे को क्वारंटाइन किया गया है।

अभी तक इतने मरीज हुए डिस्चार्ज

- **19 मार्च** : पहली मरीज केजीएमयू से डिस्चार्ज
- **छह अप्रैल** : सिंगर कनिका कपूर पीजीआइ से डिस्चार्ज
- **सात अप्रैल** : तीन मरीज केजीएमयू से डिस्चार्ज
- **10 अप्रैल** : एक मरीज केजीएमयू से डिस्चार्ज
- **11 अप्रैल** : ढाई वर्षीय बच्चा डिस्चार्ज

खेल-खेल में कोरोना को हराया : डॉ. डी हिमांशु के मुताबिक बच्चे में कोरोना के माइल्ड लक्षण थे। यह ए-कैटेगरी का था। उसमें थ्रोट इंफेक्शन ही हुआ था। श्वसनतंत्र तक वायरस नहीं पहुंच पाया। जांच में वायरल लोड काफी कम पाया गया। ऐसे में उसे सुपाच्य आहार दिया। वार्ड में उसे खेलने के लिए खिलौने भी दिए गए। कोई दवा नहीं दी गई। उसने अपनी प्रतिरोधक क्षमता के जरिए खुद ही वायरस को मात दे दी।

आरएसएस ने झारखंड में डेढ़ लाख लोगों तक पहुंचाई भोजन सामग्री

संजय कुमार, रांची

लॉकडाउन की वजह से परेशानियों में फंसी झारखंड की बड़ी आबादी को हर स्तर पर राहत पहुंचाने के निमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 4000 स्वयंसेवक मैदान में हैं। इस कार्य में संघ जुड़ी महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। झारखंड में 1000 से अधिक स्थानों पर लगाए गए राहत शिविर के माध्यम से पिछले 11 दिनों में इन स्वयंसेवकों ने जहां डेढ़ लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया है, वहीं 25000 से अधिक परिवारों तक में सूखा राशन पहुंचाने का कार्य किया है। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा व ठेला चालक, फुटपाथ पर गुजर-बसर करने वाले, घरों में अकेले रह रहे बुजुर्ग, मानसिक रूप से बीमार आदि लोगों पर स्वयंसेवकों का खास फोकस है। राहत का यह कार्य हिंदुओं के साथ-साथ मुस्लिम और ईसाई बहुल इलाकों में भी समान रूप से चल रहा है।

बताते चलें कि आरएसएस ने इस बाबत एक टॉल फ्री नंबर 1800-212-8861 जारी करने के साथ-साथ वाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए स्वयंसेवक जहां अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, वहीं समाज के सक्षम लोगों का भी सहयोग ले रहे हैं। संघ के सह प्रांत सेवा प्रमुख महेंद्र कुमार के अनुसार राहत का यह कार्य लॉकडाउन के बाद तक जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि सूखा राशन संग्रह के लिए रांची जिला मुख्यालय में 18 स्थानों पर केंद्र बनाए गए हैं। चार लोगों का एक परिवार मानकर सूखा राशन के तौर पर पांच किलोग्राम चावल, दो किलोग्राम आटा, एक किलोग्राम प्याज, दो किलोग्राम आलू के अलावा सोयाबीन बरी, चूड़ा, गुड़, सरसों तेल का पाउच आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। पांच दिनों के बाद संबंधित परिवारों के बीच फिर से वही राशन सामग्री पहुंचाई जाती है। इसके साथ ही वैसे लोगों के बीच तैयार भोजन भी वितरित किया जाता है, जो स्वयं से भोजन बना पाने में सक्षम नहीं हैं। स्वयंसेवकों ने अबतक 40 हजार से अधिक मास्क का वितरण भी संबंधित इलाकों में किया है।

मदद को बढ़े हाथ

- एक हजार से अधिक स्थानों पर राहत शिविर
- 25 हजार परिवारों तक पहुंचा सूखा राशन
- टोल फ्री नंबर 1800-212-8861 जारी

रांची स्थित अरगोड़ा में लॉकडाउन के दौरान शनिवार को जरूरतमंदों के लिए भोजन पैक करते आरएसएस के स्वयंसेवक। जागरण

टाटा ने बढ़ाया मदद का हाथ, चालू होगा रुद्रपुर अस्पताल

रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून

10 हजार एन-95 मास्क, 5000 पीपीई किट देगी कंपनी

कोरोना से लड़ रहे उत्तराखंड को जल्द राहत मिलेगी। प्रदेश में जल्द नया अस्पताल आकार लेने जा रहा है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के इस अस्पताल को चालू करने की कमान टाटा ने अपने हाथ में ली है। यही नहीं कंपनी ने भरोसा दिया है कि पुणे फैक्ट्री में वेंटीलेटर बनाए जाएंगे। इसका लाभ उत्तराखंड को भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एन-95 मास्क और पीपीई किट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर, कोरोना महामारी से लड़ाई में मदद के लिए प्रदेश सरकार ने कई उद्योगों की ओर हाथ बढ़ाया है।

स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड को रुद्रपुर में 300 बेड के नए अस्पताल से बड़ी उम्मीदें हैं। 325 करोड़ लागत से रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण को केंद्र से हरी झंडी मिल चुकी है। जल्द ही, इस संबंध में केंद्र और राज्य के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होंगे। इस बीच सरकार की कोशिश है कि रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का अस्पताल जल्द चालू हो जाए। इस मामले में टाटा कंपनी ने राज्य सरकार को बड़ा भरोसा बंधाया है। कंपनी ने अस्पताल को फंक्शनल करने का बीड़ा अपने हाथ में लिया है। कंपनी की टीम इस कार्य को संभाल चुकी है। दरअसल कोरोना महामारी का सामना करने के लिए राज्य को चिकित्सा उपकरणों की दरकार है। राज्य सरकार ने इस संबंध में कई उद्योगों से सहयोग भी मांगा है।

उद्योगों से मदद के रूप में स्वास्थ्य सुविधाएं और वेंटीलेटर समेत जरूरी उपकरण मुहैया कराने को कहा गया है। राज्य के लिए सुकून की बात है कि टाटा कंपनी ने मुंबई के बाद उत्तराखंड को सर्वाधिक वरीयता देने की बात की है। राज्य सरकार की ओर से 500 वेंटीलेटर की मांग की गई। कंपनी ने यह भरोसा दिया है कि पुणे स्थित टाटा मोटर्स में वेंटीलेटर का निर्माण किया जाएगा। कंपनी राज्य को भी वेंटीलेटर देगी। टाटा कंपनी 500 पीपीई किट मुहैया करा चुकी है, जबकि 5000 किट देने के साथ ही 10 हजार एन-95 मास्क और 25 हजार सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल प्लान तैयार किया है।

रेलवे ने यात्रियों के लिए बढ़ाई हेल्पलाइन नंबर की क्षमता

राज्यू, नई दिल्ली : लॉकडाउन के दौरान रेल यात्रियों को किसी तरह की जानकारी हासिल करने में परेशानी न हो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 138 व 139 की क्षमता बढ़ाई गई है। सोशल मीडिया के जरिये भी यात्रियों को सहायता पहुंचाई जा रही है।

कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए इन दिनों रेल परिचालन बंद है। इस स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर यात्रियों को 24 घंटे रेल संबंधी विशेषकर रिफंड को लेकर जानकारी दी जा रही है। ट्विटर व ईमेल से भी जानकारी दी जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों को स्थनीय भाषा में जानकारी दी जा रही है जिससे कि उन्हें इसे समझने में किसी तरह की दिक्कत न हो। निदेशक स्तर के अधिकारी सोशल मीडिया और ईमेल पर लोगों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं और उनके सुझावों पर नजर रख रहे हैं।

लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किसी तरह की समस्या न हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि हेल्पलाइन नंबरों की क्षमता बढ़ाने के बाद यात्रियों की परेशानी को बहुत हद तक कम कर लिया जाएगा।

सलमान खान ने मजदूरों के लिए दो ट्रक खाने का सामान भेजा

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

आमजन की मदद में सितारे लगातार आगे आ रहे हैं। अपनी दरियादिली के लिए विख्यात सलमान खान बीस हजार जरूरतमंद सिनेवर्कर्स के अकाउंट में तीन-तीन हजार रुपये की पहली किस्त भेज चुके हैं। अब उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने के लिए दो ट्रकों में खाने का सामान भेजा है। यह जानकारी विधायक जीशान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया से दो तस्वीरें साझा करके दी है। उसमें उन्होंने सलमान को टैग भी किया है।

सिद्दीकी ने लिखा है कि सलमान लोगों की मदद करने के लिए हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। दिहाड़ी मजदूरों के प्रति आपके इस योगदान के लिए धन्यवाद। कोई भूखा न सोए यह सुनिश्चित करने और कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में शामिल होने के लिए धन्यवाद।

उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के चलते सलमान इन दिनों पनवेल स्थित अपने फार्महाउस पर परिवार के कुछ सदस्यों के साथ हैं। इस बीच वह सोशल मीडिया पर सक्रिय भी हैं। उन्होंने एक दिन पहले फार्महाउस में घोड़े को चारा खिलाते हुए अपना एक वीडियो साझा किया था। शनिवार को पोस्ट किए गए इस वीडियो में वह घुड़सवारी करते नजर आए। सलमान ने कुछ देर तक घुड़सवारी की। फिर उतरकर घोड़े को कुछ देर तक गले से लगाए रखा।

सलमान खान। फाइल

उनकी फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई' को ईद पर 22 मई को रिलीज करने की योजना थी। लेकिन उसके टलने की संभावना जताई गई है। फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिल्म के दो गाने शूट होने बाकी है। उसकी एडिटिंग भी बाकी है। हालात सामान्य होने पर ही शूट संभव होगा। इससे पहले 'सूर्यवंशी और 83' की रिलीज अनिश्चितकाल तक टाली जा चुकी है।

भोपाल में जरूरतमंदों को रक्त देने के लिए भी आगे आ रहे डॉक्टर

नईदुनिया, भोपाल: भोपाल में लॉकडाउन के चलते रक्तदान शिविर नहीं लगने और रक्तदाताओं के ब्लड बैंक नहीं पहुंच पाने के कारण थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया कैंसर पीड़ितों और गर्भवती महिलाओं के लिए खून की कमी हो गई है। ऐसे में भोपाल के हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर और नर्स रक्तदान कर रहे हैं।

कोरोना नियंत्रण में लगे होने के बाद भी समय निकालकर डॉक्टर बारी-बारी से रक्तदान कर रहे हैं। इनके अलावा संत निरंकारी मिशन से जुड़े 10 लोगों ने भी हमीदिया अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया है। यही वजह है कि हमीदिया अस्पताल के ब्लड बैंक में हफ्तेभर के भीतर पैक रेड ब्लड सेल (आरबीसी) 50 यूनिट से बढ़कर 170 यूनिट हो गया है। हमीदिया अस्पताल के ब्लड बैंक ऑफिसर डॉक्टर उमेंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि रुटीन की सर्जरी अभी नहीं हो रही हैं, इसलिए खून की मांग पहले से कम है, लेकिन खून की कमी वाली बीमारियों के मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए लगातार खून की जरूरत पड़ रही है। अब अस्पताल के डॉक्टर ही इसके लिए आगे आ रहे हैं।

कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित युवा भी महामारी के खिलाफ मोर्चे पर तैनात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्वास्थ्य सेवा में प्रशिक्षित एक लाख से ज्यादा नौजवान साबित हो रहे हैं अहम

जन शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं मास्क

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण पाने वाले युवा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षण पाए लगभग एक लाख युवाओं की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी है, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर की देखभाल से लेकर कोरोना अस्पतालों में प्रबंधन समेत कई तरह के कार्यों में लगाया गया है। इसके अलावा जन शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में मास्क बनाकर वितरित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार कौशल विकास मंत्रालय ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित एक लाख से अधिक युवाओं की सूची दी है। इनमें 92,040 प्रशिक्षु, 373 रेडियोलॉजी एक्सपर्ट, 989 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, 299 टेक्नीशियन, 530 फ्रंटलाइन वर्कर, 10,172 जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और 334 प्लेबोटोमी टेक्नीशियन शामिल हैं। कोरोना के मरीजों के इलाज से लेकर क्वारंटाइन सेंटर में संदिग्ध मरीजों की देखभाल तक में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में जनशिक्षण संस्थानों को मास्क बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। कौशल विकास मंत्रालय के अनुसार अभी तक इन केंद्रों में चार लाख से अधिक मास्क बनाकर वितरित किए जा चुके हैं और प्रशिक्षित युवाओं के सहयोग से जल्दी ही इस महामारी से पार पा लिया जाएगा।

आइटीआइ क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील

कौशल विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने इस बात पर खुशी जताई कि 'आपदा के इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे आइटीआइ और एनएसटीआइ जैसे संस्थान इस महामारी के खिलाफ जंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।' कोरोना वायरस से मरीजों की बढ़ने की आशंका के मद्देनजर सभी राज्यों में क्वारंटाइन सेंटर और विशेष अस्पतालों को तैयार करने का काम जोर-शोर से जारी है। ऐसे में कौशल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आइटीआइ और एनएसडीआइ की सूची सौंपते हुए कहा है कि जरूरत पड़ने पर इनका क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें कई स्थानों को क्वारंटाइन सेंटर में परिवर्तित भी किया जा चुका है।

अध्ययन

इसमें मौजूद विशेष रसायन लॉरिक एसिड खत्म कर सकता है कोरोना वायरस का खेल, दुनिया के जानलेवा 14 वायरसों पर हो चुका है इसका सफल प्रयोग, कोविड-19 के खिलाफ आजमाने की तैयारी में मेडिकल जगत

नारियल का तेल करेगा कोरोना को फेल!

हिमांशु अस्थाना, वाराणसी

नारियल के तेल में पाया जाने वाला एक विशेष अम्ल कोरोना वायरस का खेल खत्म कर सकता है। अब तक अनेक घातक रोगाणुओं पर यह अम्ल अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। मेडिकल जगत में इसे लेकर मंथन हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिक भी इसे लेकर सरकार सक्रिय हुए हैं।

स्वस्थ समाज

नारियल के तेल में पाये जाने वाले लॉरिक एसिड को मोनो लॉरिन में बदलकर यदि कोविड-19 पर प्रयोग करें तो यह इस वायरस के प्रोटीन निर्मित बाहरी आवरण को भेद कर इसे नष्ट कर सकता है। इसका प्रयोग अभी तक एचआइवी, रूबोला, इन्फ्लूएंजा, सारकोमा, हरपीज, निमोना, लिंफोट्रिक जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक 14 रोगाणुओं पर सफल रूप से हो चुका है।

आइआइटी, बीएचयू स्थित मालवीय उद्यमी संवर्धन एवं नवप्रवर्तन केंद्र के इंक्यूबेट डॉ. सुमित सक्सेना ने भारत सरकार से इसपर लैब परीक्षण के लिए अनुमति मांगी है ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ यदि यह परीक्षण खरा उतरे तो जल्द से जल्द दवा विकसित की जा सके। डॉ. सुमित के मुताबिक जिन खतरनाक 14 वायरस पर मोनो लॉरिन का परीक्षण किया गया उनके बाहरी आवरण पूर्णतः नष्ट हो गए। डॉ. सक्सेना बताते हैं कि लॉरिक एसिड को मोनो लॉरिन में बदलने का काम केवल मनुष्य के लीवर में ही होता है, जबकि नारियल में 50 प्रतिशत तक लॉरिक एसिड पाया जाता है, जिसे मोनो लॉरिन में बदला जा सकता है। डॉ. सुमित ने बताया कि कोविड-19 की संरचना को यदि ध्यान से देखें तो इसके कैप्सूल (खोल) के बाहर कई कांटे होते हैं, जिन्हें प्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं। कोविड-19 के यही स्पाइक्स मानव के फेफड़ों पर जाकर धंस जाते हैं, जिससे यह घातक साबित होता है। मोनो लॉरिन वायरस के लिपिड बाइ लेयर (ऊपरी परत) में प्रविष्ट होकर आवरण का ही अंत कर देता है, जिन पर ये कांटेदार संरचनाएं बनी रहती हैं। बाहरी आवरण के नष्ट होने के बाद इसके भीतरी हिस्से में आरएनए (राइबो न्यूक्लिक एसिड) ही शेष रहता है, जिसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता स्वतः ही खत्म कर सकती है।

> परीक्षण सफल होने पर मोनो लॉरिन के साथ हल्दी के करक्यूमिन को मिलाकर कैप्सूल के रूप में कोरोना को मात देने वाली दवा विकसित की जा सकेगी। नारियल के अलावा लॉरिक एसिड की मात्रा मां के दूध में भी काफी मात्रा में पाई जाती है, वहीं बकरी के दूध और पाम ऑयल में भी यह मिलता है। आयुष मंत्रालय से अनुमति मिलते ही इस कार्य को जल्द शुरू करेंगे।
> - डॉ. सुमित सक्सेना, फाउंडर, हील वेंचर बायोसाइंस

प्रतीकात्मक। सौ. एसएफ

> नारियल के तेल में लॉरिक एसिड के महत्व पर कई शोध हुए हैं। इसमें वायरस की मेंब्रेन ब्रेक (आवरण नष्ट) करने की क्षमता बताई गई है। साथ ही छोटे-छोटे वायरस को समूह बनाने से भी रोकने में यह मददगार बताया गया है। कोरोना वायरस का आवरण प्रोटीन, लिपिड और फैटी एसिड से निर्मित है, जो तैलीय होता है। इसे मोनो लॉरिन भेद सकता है। लैब परीक्षण कर कोविड-19 की दवा खोजने पर काम हो सकता है।
> - डॉ. मनोदीप सेन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, उप्र

रेलवे ने 5000 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदला

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेलवे ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए 5000 डिब्बों को पृथक वार्ड में तब्दील किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। यह जानकारी शनिवार को अधिकारियों ने दी। मंत्रालय ने बताया कि महामारी से निपटने के लिए रेलवे ने 20 हजार डिब्बों को पृथक वार्ड में बदलने का लक्ष्य तय किया है। इनमें से 80 हजार बिस्तरों के साथ पांच हजार डिब्बे तैयार हैं।

इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, 'इन डिब्बों को तब्दील करने का विचार यह था कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां कोविड-19 रोगियों की देखभाल की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय जब हमें निर्देश देगा और हम इन डिब्बों को वहां भेज देंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि वे अच्छी हालत में हों। उन्होंने कहा कि इस तरह के डिब्बों में इस्तेमाल के लिए रेलवे चादर भी उपलब्ध करा सकता है लेकिन वे केवल एक बार इस्तेमाल योग्य होंगी। अधिकारी ने कहा कि रेलवे इस पर भी विचार कर रहा है कि गैर वातानुकूलित इन डिब्बों को गर्मी में किस तरह ठंडा रखा जाए।

अधिकारियों ने कहा कि रेलवे के अंदर चर्चा चली कि क्या लाइफ लाइन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं जहां डाक्टर हर तरह के रोगियों की देखभाल करें या दुर्घटना राहत रेलगाड़ी जैसी व्यवस्था हो जो ऑपरेशन थिएटर से लैस होती हैं। बहरहाल, बाद में इस तरह का विचार त्याग दिया गया क्योंकि इस तरह की व्यवस्था करने में ज्यादा समय लगता। अभी जो व्यवस्था की गई है उसमें हर ट्रेन में दस डिब्बे होंगे और हर डिब्बे में 16 रोगियों को रखने की क्षमता है। इन ट्रेनों में चिकित्साकर्मियों के लिए एक वातानुकूलित डिब्बा भी जोड़ा जा सकता है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

सख्ती सूचकांक : अव्वल हैं हम

कोरोनो को हराने के लिए सरकारों द्वारा उठाए कदमों पर ऑक्सफोर्ड ने सख्ती सूचकांक तैयार किया है। इसमें भारत शीर्ष पर है।

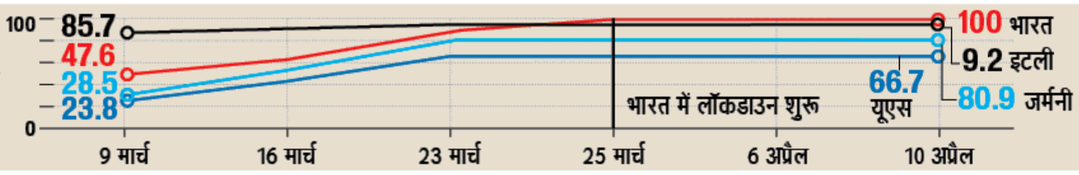

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

7 दैनिक जागरण

12 अप्रैल 2020

सबका राजधर्म

शिवानंद द्विवेदी
सीनियर रिसर्च फेलो, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली

कोविड-19 को हराने के लिए हम भले 'शारीरिक दूरी' बना रहे हैं, लेकिन संवेदनाओं की पृष्ठभूमि में हम सवा सौ करोड़ देशवासी एक-दूसरे का हाथ पकड़े चट्टान बनकर खड़े हैं।

कोविड-19 के प्रकोप से ठहर सी गयी दुनिया के बीच यह जाहिर हुआ है कि भारत आशाओं की अनुभूति को हर पल जिंदा रखने वाला देश है। यह इस देश की सकारात्मक ऊर्जा है कि यहां के लोग कठिनाइयों से अवसाद में जाने की बजाय नए रास्तों पर आगे बढ़ने का अवसर तलाश लेते हैं। संयम, सेवा, समर्पण, सहयोग, संतुष्टि और संकल्प का विलक्षण संयोग देश ने इस कठिन दौर में दिखाया है। लॉकडाउन की कठिनाइयों में नवाचार के नए-नए प्रयोग दिख रहे हैं। निश्चित ही यह सेवा और समर्पण के लिए मजबूत मन से संकल्पित होने का दौर है।

इस विकट परिस्थिति के खिलाफ खड़े होने की जिम्मेदारी भी सवा सौ करोड़ कंधों पर है। याद रखना चाहिए कि कोविड-19 के खिलाफ इस महायुद्ध में अमेरिका और यूरोप के देशों जैसी दुनिया की शीर्ष महाशक्तियां लाचार नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य और सम्पन्नता के विश्वस्तरीय मॉडल निरीह और बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसे में वैश्वीकरण में सिमट चुकी दुनिया वाले इस दौर में भारत का भी इससे अछूता रह जाना संभव नहीं था, किंतु संतोष और राहत की बात है कि हम और हमारा देश इस अदृश्य परजीवी के खिलाफ दुनिया के तमाम शक्ति संपन्न देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में लड़ रहे हैं। यद्यपि संक्रमण के मामलों में अब तेजी आई है, फिर भी यह दर यूरोपीय देशों और अमेरिका से अभी कम है। अमेरिका और ब्राजील जैसे देश भारत से मदद मांग रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोविड-19 के विरुद्ध भारत के कदमों में उबरने की आस दिख रही है। दुनिया के श्रेष्ठतम चिकित्सा प्रणाली वाले इटली और अमेरिका की स्थिति देखने के बाद यह वैश्विक संगठनों के लिए चकित करने वाली बात है कि भारत इस वायरस पर तुलनात्मक रूप से कैसे नियंत्रण कर सका है?

इस सवाल के जवाब को समझते हुए सरकार की मानवीयता आधारित नीति और नागरिकों की संकल्प शक्ति का समन्वय नजर आता है। इस वायरस के आसन्न संकट के समय मोदी सरकार के सामने दो विकल्प थे। पहला, सरकार या तो देश के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए मानव जीवन को दूसरी वरीयता पर रखती, या दूसरा कि सबकुछ बंद करके 'मानव जीवन' की रक्षा करने की नीति पर चलती। सरकार ने दूसरा विकल्प चुना और 'मानव जीवन' की रक्षा को ध्येय मानकर इस लड़ाई में आगे बढ़ते हुए 'संपूर्ण लॉकडाउन' घोषित किया। यह वह कदम था, जिसका साहस दुनिया का कोई विकसित देश नहीं दिखा पाया था। उपनिषद वाक्य है- 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्, अर्थात शरीर ही सभी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। मोदी सरकार ने इसी को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक हितों को दूसरे पायदान पर रखा। वहीं मोदी सरकार के इस कदम पर देश की जनता ने भी वही भाव दिखाया, जिसकी अपेक्षा मानवीय संवेदनाओं वाले समाज से की जाती है। सतर्कता, संयम, सेवा, समर्पण और अडिग संकल्प का भाव सवा सौ करोड़ जनता वाले देश में जिस ढंग से दिखा है, वह मिसाल है।

एक ऐसा दौर जब 'शारीरिक दूरी' आग्रह का विषय बन गया है, वैसे में अकेलापन, अवसाद और नकारात्मकता के घर करने का भय संभावी था, किंतु जनता कर्फ्यू के दिन जिस तरह से 'कोरोना वैरियर्स' के अभिवादन में देश ने अपनी चौखट पर एकजुट होकर करतल ध्वनि से कश्मीर से कन्याकुमारी तक के आसमान को गुंजायमान किया, वह इस धरती की जीवंत चेतना का परिचायक बना। कठिन दौर में यह कम होता है जब नेतृत्व का जनता पर और जनता का नेतृत्व पर इतना अगाध विश्वास हो। प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील पर देश 5 अप्रैल की रात 9 बजे एकजुट नजर आया, जब हर घर से उम्मीद की रौशनी जगमगा उठी।

इस आपदा ने हमें बताया है कि यह देश आशाओं के बल से बलवान है। सेवा इसके आचरण का नैसर्गिक तत्व है। संकल्प इसके विजय का बीजमंत्र है। एकजुटता इसके चरित्र की जीवटता है। इसकी मिट्टी में जीत का जज्बा घुला हुआ है। इसकी सभ्यता अपराजेय है, इसकी सांस्कृतिक अट्टालिकाएं अभेद्य हैं। कोविड-19 को हराने के लिए हम भले 'शारीरिक दूरी' बना रहे हैं, लेकिन संवेदनाओं की पृष्ठभूमि में हम सवा सौ करोड़ देशवासी एक-दूसरे का हाथ पकड़े चट्टान बनकर खड़े हैं। यह देश कभी हारा नहीं है। इसबार भी नहीं हारेगा।

शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 'जान भी जहान भी' की बात कहकर लॉकडाउन तो आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए समृद्ध और स्वस्थ भारत के दोनों पहलुओं पहलुओं को जरूरी बताया। इससे पहले देश को संबोधित करते हुए घर में रहने और शारीरिक दूरी के नियम पालन को कोरोना की रामबाण काट करार दिया था। अब जान के साथ जहान भी जरूरी हो चला है। क्योंकि लड़ाई विकट है। लोग विकल हैं। चीन से साढ़े तीन महीने पहले चला चंद माइक्रोमीटर का एक अदना सा वायरस दुनिया को घुटने टिकवाने पर आमादा है। यह बात सही है कि भारत में अभी कोरोना वायरस से संक्रमित लोग और मरने वालों की संख्या अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देशों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन जिस हिसाब से इन दोनों मदों में इजाफा हो रहा है, भयभीत करने वाला है। जितनी बर्बरता के साथ यह वायरस आगे बढ़ रहा है, उतनी ही शिद्दत के साथ इंसानियत अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सामने आ रही है। शायद इस पिद्दी से वायरस को इंसानों की जीवटता, संकल्प और नवोन्मेष का इल्म नहीं है। धरती पर यह एकदम नया है। अपने पूर्वजों के इतिहास से इसे सीखना चाहिए। वे लोग भी जब आए तो कोहराम बरपाना शुरू किए, लेकिन कुछ ही दिनों में जैसे ही उनकी चाबी तलाश ली गई, इस ग्रह से रफूचक्कर होने में देर नहीं लगाई। तेरा क्या होगा कोरोना? वही होगा जो तेरे पूर्वजों का होता आया है। कुछ ही दिनों की देर है। टीका आते ही तुम्हारा राम नाम सत्य तय है। तब तक हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति हमारे अस्तित्व की ढाल बनी रहेगी। घरों में रहकर, शारीरिक दूरी बनाकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइज के सारे दिशानिर्देशों का पालन करके कष्ट सह लेंगे, लेकिन कोरोना बिना तुम्हारा समूल नाश किए चैन से नहीं बैठेंगे। जान के साथ-साथ जहान यानी अर्थव्यवस्था की भी चिंता हमारे हर कदम से परिलक्षित होगी। तुमसे निपटने के साथ ही समृद्धि को संवारना ही असली राष्ट्रभक्ति होगी। समझे कुछ। इंसानियत जिंदाबाद थी, है और रहेगी। आमीन।

जान भी जहान भी

अब देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए जान भी जहान भी, दोनों पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अब देश का प्रत्येक व्यक्ति दोनों बातों की चिंता करते हुए अपने दायित्व निभाएगा, सरकार और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करेगा

प्रधानमंत्री मोदी

(11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने के दौरान)

दिन सांसत के

चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित पहले मामले से अब तक सौ दिन बीत चुके हैं। इस दौरान 15 लाख से ज्यादा लोग दुनिया के 192 देशों में संक्रमित हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा भी लाख को छूने जा रहा है। अरबों की संख्या में लोग घरों में कैद होने को विवश हैं। अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट और रोजगार सब रसातल में पहुंचने का रिकार्ड बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस वायरस ने कैसे दुनिया को अपने नन्हें से आकार में समेट लिया है।

पहला दिन
31 दिसंबर 2019
000 मामले
00 मौतें

चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया कि उसके यहां निमोनिया के 44 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वजह अज्ञात है। ये मामले 31 दिसंबर से तीन जनवरी के दरम्यान आए। हालांकि यहां निमोनिया के मामले दिसंबर और संभवत: वुहान में नवंबर में ही दिख गए थे, लेकिन यह पहला मौका था जब इस रहस्यमयी बीमारी की तरफ दुनिया का ध्यान गया।

7वां दिन
6 जनवरी, 2020
53 मामले
00 मौतें

चीनी वैज्ञानिकों ने एक वायरस को अलग किया जिसे बाद में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार के रूप में पहचाना गया।

10वां दिन
9 जनवरी 2020
63 मामले
01 मौतें

वायरस ने पहली जान ली जिसकी घोषणा चीन ने दो दिन बाद की।

24वां दिन
23 जनवरी
654 मामले
18 मौतें

वुहान में लाकडाउन हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन को इंसान से इंसान में संक्रमण का पता चला।

32वां दिन
31 जनवरी
9927 मामले
213 मौतें

ब्रिटेन ने अपने पहले संक्रमण के मामले की घोषणा की

43वां दिन
11 फरवरी
44,802 मामले
1,113 मौतें

रोग को कोविड-19 नाम दिया गया।

46वां दिन
14 फरवरी
66,885 मामले
1,523 मौतें

अफ्रीका में मामले सामने आए। फ्रांस में इस संक्रमण से पहली मौत हुई।

55वां दिन
23 फरवरी
78,958 मामले
2,469 मौतें

कोरोना से इटली में तीन मौतें हुईं। वहां पर तमाम आयोजन रद होने लगे।

69वां दिन
8 मार्च
1,09,821 मामले
3,802 मौतें

इटली का सबसे प्रभावित इलाका लामबार्डी लाकडाउन के हवाले हुए। ईरान में बुरी तरह से संक्रमण फैला।

72वां दिन
11 मार्च 2020
1,25,875 मामले
4,615 मौतें

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीमारी को महामारी घोषित की।

76वां दिन
15 मार्च
1,67,454 मामले
6,440 मौतें

स्पेन में एक दिन के भीतर सौ मौतें हुईं। इससे भी बुरा दौर आने को था।

86वां दिन
25 मार्च
4,67,653 मामले
21,181 मौतें

अमेरिकी कांग्रेस ने दो लाख करोड़ डालर के आपातकालीन कार्यक्रम को मंजूरी दी।

88वां दिन
27 मार्च
5,93,291 मामले
27,198 मौतें

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जानसन पाजिटिव पाए गए

94वां दिन
2 अप्रैल, 2020
10,13,320 मामले
52,983 मौतें

वायरस के संक्रमितों के आंकड़े ने दस लाख को पार किया। मौतें भी पचास हजार को पार हुईं।

100वां दिन
8 अप्रैल
15,11,104 मामले
88,000 मौतें

दुनिया के 192 देशों में फैला वायरस/ वायरस के उद्गम स्थल चीन के वुहान को फिर से खोला गया।

यहां से फैल रही उम्मीद की किरण

सख्त लॉकडाउन उपायों ने इटली, स्पेन, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों में कोरोनो वायरस के प्रसार को धीमा किया है। जबकि अमेरिका, जिसे धीमी प्रतिक्रिया के लिए कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी है, करीब 5 लाख संक्रमण के मामले सामने आने के बाद महामारी का केंद्र बन गया है। साथ ही यहां पर करीब 17,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। जांस हापकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार, जब किसी देश में पिछले दिन की तुलना में कम नए कोविड-19 के मामले उभरते हैं तो यह संकेत है कि संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है।

न्यूजीलैंड : 23 मार्च को देश सीधे दूसरे से चौथे आपातकाल स्तर पर पहुंच गया। इसके तहत, स्कूल और गैर-आवश्यक व्यवसाय बंद किए गए और लोगों को घर पर रहने के लिए कहा गया। यहां तक की घर में रहने वालों को भी दो मीटर की दूरी रखने के लिए कहा गया। अभी तक न्यूजीलैंड में कुल 1283 मामले सामने आए हैं और दो मौतें हुई हैं। आलम यह है कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के कारण इस्तीफा देने के लिए कहा गया।

जर्मनी : संक्रमितों की संख्या 1,18,181 तक पहुंच चुकी है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 2607 है। मौतों के आंकड़ों को थाम देने के लिए परीक्षण, पहचान और पहुंचना, सरकार द्वारा सख्त कदम और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वजहें रहीं। 22 मार्च से लॉकडाउन है और यह चौथा देश था जहां संक्रमितों की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई। देश 19 अप्रैल तक सामान्य हालात में पहुंचना चाहता है। जर्मनी में 27 मार्च को एक ही दिन में 6933 नए मामले सामने आए और 2 अप्रैल को 6922 मामले।

ईरान : 30 मार्च को 24 घंटे में ही संक्रमण के 3,186 नए मामले सामने आए। हालांकि अब ईरान में रोजाना सामने आने वाले संक्रमण के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और धर्मस्थलों को बंद कर दिया है। अब तक पूर्ण लॉकडाउन से कतराते रहे ईरान ने सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जांस हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार, ईरान मामलों की संख्या (66,220) के मामले में सातवें स्थान पर है।

अमेरिका : करीब पांच लाख संक्रमण के मामलों की पुष्टि की है। देश के कुछ हिस्सों के साथ कोरोनो वायरस के हॉटस्पॉट के रूप में उभरा कैलिफोर्निया अलग ही मिसाल पेश कर रहा है। 4 अप्रैल को सर्वाधिक 33,264 नए मामले सामने आने के बाद दैनिक संक्रमण लगातार चार दिनों में कम हुआ है और यह 28,222 से 29,000 के बीच रहा है। अमेरिका में मौतों की संख्या मंगलवार को एक ही दिन में 1,900 के रिकॉर्ड के साथ 12,700 को पार कर गई। अमेरिका में केवल कुछ राज्यों जैसे कैलिफोर्निया ने 19 मार्च की शुरुआत में 'घर पर रहना' के आदेश जारी किए थे।

स्पेन : स्पेन 15 मार्च से लॉकडाउन में है। अब तक 157053 मामले सामने आ चुके हैं। 15477 मौतें हो चुकी हैं। 24 मार्च को एक ही दिन में 9,000 से अधिक मामले सामने आए। हालांकि अच्छी बात यह है कि स्पेन में 1 अप्रैल से लगातार पांच दिनों तक दैनिक मामलों में गिरावट देखी गई है।

नीदरलैंड्स : नीदरलैंड्स ने 'लक्षित लॉकडाउन' लगाया है और भीड़ की प्रतिरक्षा के विचार को अपनाया है। 21,903 कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है। 27 फरवरी को पहले कोविड-19 मामले की पुष्टि के बाद 27 मार्च को नीदरलैंड में नए संक्रमण के 1179 मामले सामने आए। उसके बाद, लगातार आठ दिनों तक रोजाना आने वाले मामलों में गिरावट देखी है, जिसका आंकड़ा 900 से 1100 के बीच रहा है।

इटली : एक महीने से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन है। सर्वाधिक मामले वाले देशों में यह तीसरे स्थान पर है। अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि, नए मामलों में कमी आने के बाद प्रकोप को एक स्तर नीचे कर दिया गया है। 20 मार्च को इटली में एक ही दिन में नए संक्रमणों की संख्या 6,000 पहुंच गई थी।

जनमत

हां 99% नहीं 01%

क्या कोरोना की जंग में अनमोल मानव संसाधनों को बचाकर हम फिर से अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई आसानी से करने में सक्षम होंगे?

हां 95% नहीं 05%

क्या पूर्व में पैदा हुई महामारियों से लड़ने की इंसानी जिजीविषा कोरोना महामारी के समूल नाश में दुनिया के लिए संबल बनी हुई है?

आपकी आवाज

कोरोना को हराने और आर्थिक भरपाई करने में तभी सक्षम होंगे, जब हम सभी घर पर रहें, कोरोना को हराने के लिए बनाएं नियमों का पालन करें। राजेश कुमार

महामारियों के खिलाफ मानव दवा बनाने में भी सफल हुआ है। वर्तमान में इस घातक कोरोना का समूल नाश भी देर सबेर अवश्य ही होगा। मुन्ना स्वर्णकार

वर्तमान के उन्नत वैज्ञानिक समय में तो तमाम राष्ट्र परस्पर सहयोग के लिए उद्यत हैं। दुनिया को यह भरोसा रहना ही चाहिए कि इस महामारी का भी समूल नाश निश्चित है। इंसानी हिम्मत और हौसला बड़ी से बड़ी चुनौती को जीत में बदल देता है। कोरोना कहर के दौर में भी हमारी धैर्यता, सूझबूझ, संयमितता, अनुशासन और जिजीविषा कोरोना को पछाड़ रही है और हमें अब तक सामुदायिक संक्रमण से दूर रखा है। यह संबलता ही जीत का परिचायक है। डॉ. हर्ष वर्द्धन

जारी है जंग

हमारे वैज्ञानिकों ने सालों में हासिल किए जाने वाले लक्ष्य की अवधि को अपनी अथक मेहनत से महीनों में बदल दिया है। उनके दृढ़निश्चय से ही कोरोना के इलाज और वैक्सीन की तलाश ह्यूमन ट्रायल के चरण तक पहुंच गई है। इलाज चार से पांच माह में मिलने की उम्मीद जग गई है। हालांकि तब तक कोरोना और धरती के भगवानों के बीच जंग जारी रहेगी। इस जंग में हम और आप महज शारीरिक दूरी के सिद्धांत व साफ-सफाई के काम को अंजाम देकर अपना योगदान दे सकते हैं।

आपातकाल में ऐतिहासिक फैसले

सामान्य परिस्थिति में साधारण फैसले लिए जाते हैं और असामान्य में ऐतिहासिक फैसले किए जाते हैं। सामान्य परिस्थिति में किसी रोग का इलाज या वैक्सीन खोजने में वर्षों बरस लग जाते हैं। टीबी हो या एचआइवी या फिर जेई हमने दो से चार दशक की मेहनत के बाद ही इनकी वैक्सीन खोजी। पश्चिमी देशों में सरकारों और गैर लाभकारी संगठनों की मदद से कंपनियों ने फुर्ती दिखाई और अपने तमाम संसाधन इस ओर लगा दिए।

बढ़ा दिए हैं पुख्ता कदम

दुनिया की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी नोवेक्स ने मई के दूसरे पखवाड़े में ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिका के मैरीलैंड स्थित कंपनी के शोधकर्ताओं ने विश्वास जताया कि इम्यून सिस्टम पर उसकी दवा ने लैब में किए गए परीक्षणों और जानवरों पर शानदार असर दिखाया है। इस दवा से ऐसे एंटीबॉडी पैदा करने में मदद मिली। उम्मीद है कि उसकी दवा साल के अंत तक बाजार में आ जाएगी।

न रह जाए कोई कसर

स्टेम सेल थैरेपी पर काम कर रही अमेरिकी कंपनी मेसोब्लास्ट ने भी घोषणा कर दी है कि वह 240 मानवों पर अपनी दवा का ट्रायल करेगी। उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआइएच) का साथ भी मिल गया है। कंपनी ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों में पैदा होने वाले इम्युन रिएक्शन (रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण पैदा होने वाली दिक्कतों) का इलाज सफलतापूर्वक खोजा है।

मोडेरना ने शुरू किए ट्रायल

मोडेरना ने क्लीनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इनोवियो ने दवा का पहला डोज एक वॉलिंटियर को दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन सितंबर से ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है। बेयलर कॉलेज ऑफ मेडिसन ने भी वैक्सीन में सफलता का एलान किया है, जिसे अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनेस्ट्रेशन से इजाजत का इंतजार है।

ये दशाएं बदलेंगी फिजाएं

हर कोई अपने हिसाब से लॉकडाउन के पक्ष और विपक्ष में तर्क देता सुना जा सकता है। इन सबके बीच कुछ राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार को इसे बढ़ाने के लिए कहा है। लॉकडाउन उठाने के लिए सही समय क्या हो सकता है, इसके लिए कुछ बिंदुओं पर विचार के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आइए इन पर गौर करें।

यदि हमारे पास टीका है तो

यदि हम आबादी के करीब 60 फीसद हिस्से का टीकाकरण करने में कामयाब हो जाएं तो ये बीमारी महामारी नहीं बन सकती। टीके में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन में रहने के लिए यह बहुत लंबी अवधि है।

जब पर्याप्त लोगों में हो प्रतिरक्षा

वायरस पर्याप्त लोगों को संक्रमित करता है, जो फिर ठीक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उनमें खुद ब खुद प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। लेकिन भीड़ की प्रतिरक्षा को बनने में ही सालों लग सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह विचार काम करेगा या नहीं। अन्य कोरोना वायरस पुनरावृत्ति करने के लिए जाने जाते हैं।

जब हमारे पास योजना हो

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव टेड्रोस ऐडहेनॉम गेब्रीयेसोस के अनुसार संक्रमण को रोकने और जीवन बचाने के लिए अधिक सटीक और लक्षित उपाय आवश्यक है।

जब हम तैयार हों

14 दिनों के लिए मामलों में निरंतर कमी, रोगियों के इलाज में सक्षमता, लक्षण वालों और उनके संपर्कों के परीक्षण व निगरानी में समर्थ हों।